● वर्ष-6
● अंक-38
रायपुर, गुरुवार
17 सितंबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> बस्तर-सरगुजा सहित प्रदेश...

झीरम घाटी नक्सली हमले में 10 दोषियों को फांसी की सजा

29 लोगों की हत्या पर 13 साल बाद आया फैसला

रायपुर । झीरम घाटी हत्याकांड मामले में जगदलपुर की एनआईए कोर्ट ने 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर नक्सली हमला हुआ था। इसमें कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 29 लोगों की मौत हुई थी।

करीब 13 साल चली सुनवाई के दौरान 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया गया। जज ने अपने फैसले में कहा है कि आदेश की पुष्टि हाईकोर्ट करेगा। दोषियों को 30 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार है। अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने सजा कम करने की दलील दी थी।

सभी दोषी अभी केंद्रीय जेल में बंद हैं। अदालत ने कुल 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई की थी। मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी, जिसके बाद अदालत ने शेष 10 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी रखी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने वर्ष 2015 में लगभग 1000 पन्नों का आरोप पत्र अदालत में पेश किया था। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों का दोष साबित करने के लिए पूरी सुनवाई के दौरान 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए थे।

10 आरोपियों को फांसी की सजा

प्रमिला मोडियाम, सुमित्रा पुनेम, कोसा कवासी, मुक्का मांडवी, मड़कामी देवा, आयत मरकाम, बजामी सेना, चैतू लेकाम, जोगा मड़कामी, महादेव नागा

25 मई 2013 को हुआ था झीरम नक्सली हमला

13 साल पहले बस्तर में कांग्रेस अपनी परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी। 25 मई 2013 की शाम यह यात्रा सुकमा की ओर से लौट रही थी। काफिला जब दरभा क्षेत्र की झीरम घाटी से गुजर रहा था, तभी माओवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। हमले की शुरुआत आईईडी विस्फोट से हुई। इसके बाद सड़क पर पेड़ गिराकर रास्ता बंद किया गया और जंगल से काफिले पर गोलियां बरसाई गईं। कुछ ही देर में पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। नक्सलियों ने नेताओं और सुरक्षाकर्मियों को अलग-अलग कर दिया। माओवादियों का खास निशाना महेंद्र कर्मा थे। नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और कई अन्य लोगों की भी हत्या कर दी गई। एक ही हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश नेतृत्व के कई प्रमुख नेताओं की मौत हो गई थी। झीरम हमला अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके लिए कई सप्ताह पहले से तैयारी चल रही थी।

उच्च न्यायालय में अपील की संभावना

इधर, एनआईए की विशेष अदालत से दोषियों को मृत्युदंड की सजा मिलने के बाद अब मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया पर सबकी निगाहें हैं। आरोपी पक्ष फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

मिनपा से दरभा कैसे बदला टारगेट

माओवादियों की शुरुआती योजना सुकमा के मिनपा क्षेत्र में सुरक्षा बलों की चौकी पर हमला करने की थी। फरवरी 2013 में बीजापुर के पिडिया गांव में हुई बैठक में रणनीति बदली गई। बैठक में फैसला हुआ कि हमला मिनपा के बजाय दरभा क्षेत्र में किया जाएगा। यह निर्णय वरिष्ठ माओवादी कमांडर देवजी की मौजूदगी में लिया गया था।

किसान दिवस पर राज्य स्तरीय कृषक संगोष्ठी संपन्न

रायपुर। भारतीय कृषि परंपरा में भगवान श्री बलराम जी का विशेष स्थान है। भगवान बलराम को हल एवं कृषि के प्रतीक के रूप में स्मरण किया जाता है। उनके हाथों में सुशोभित हल किसान के श्रम धरती से उसके गहरे संबंध और कृषि संस्कृति का प्रतीक है। भगवान बलराम जयंती किसान के परिश्रम, कृषि के महत्व तथा धरती और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का स्मरण कराती है। इसी भावना को केंद्र में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भगवान बलराम दिवस को प्रदेश में किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में स्वामी विवेकानंद सभागार, कृषि महाविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में भगवान श्री बलराम जयंती-किसान दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में दलहन, तिलहन एवं प्राकृतिक खेती विषय पर राज्य स्तरीय कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

फैसला वापस लेनी की मांग

यूपीआई चार्ज मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में 2,000 रूपए से अधिक के कुछ पी 2 एम यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाने के सरकारी फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में इस कदम को मनमाना और वित्तीय बोझ डालने वाला बताते हुए तय की गई सीमाओं और दरों के पारदर्शी आधार पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें केंद्र सरकार के उस हालिया फ़ैसले को चुनौती दी गई है जिसके तहत 2,000 रूपए से ज़्यादा के कुछ खास व्यक्ति से व्यापारी यूपीआइ ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने की अनुमति दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह कदम बिना किसी उचित कानूनी सुरक्षा के मनमाना और देशव्यापी वित्तीय बोझ डालता है। वकील आशुतोष दुबे के ज़रिए वकील

अंजन दत्ता द्वारा दायर इस याचिका में 14 सितंबर, 2026 को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10 के तहत जारी गैज़ेट नोटिफिकेशन और 15 सितंबर को घोषित उस फ़्रेमवर्क को चुनौती दी गई है जिसके तहत ज़्यादा वैल्यू वाले कुछ खास व्यक्ति से व्यापारी यूपीआइ ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जाएगा। इस फ़्रेमवर्क के तहत, 2,000 रूपए से ज़्यादा के योग्य व्यक्ति से व्यापारी यूपीआइ ट्रांज़ैक्शन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगेगा, जिसमें 75,000 रूपए और उससे ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन के लिए अधिकतम चार्ज 300 होगा। कुछ खास सेक्टर के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं। यह फ़्रेमवर्क 15 अक्टूबर से लागू होने वाला है। याचिकाकर्ता ने नए चार्ज और कैटेगरी तय करने के तरीके को चुनौती दी है। उनका तर्क है कि सरकार ने 2,000 रूपए के ट्रांज़ैक्शन की लिमिट, 1 लाख की मंथली-रिसीट कैटेगरी, अलग-अलग सेक्टर के रेट और 75,000 रूपएकी कैप के पीछे के डेटा या सिद्धांतों को सार्वजनिक नहीं किया है। याचिका में लिमिट से ठीक ऊपर और नीचे के ट्रांज़ैक्शन के बीच के अंतर पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिका के अनुसार, 2,001 रूपएके ट्रांज़ैक्शन पर प्रतिशत-आधारित चार्ज लगेगा, जबकि 2,000 रूपए के ट्रांज़ैक्शन पर नहीं। इससे एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसे क्लिफ (अचानक बड़ा बदलाव) कहा जा सकता है।

यूपी : वाल्मीकि सियासत में जगह बनाने में जुटीं रोहिणी घावरी

चन्द्रशेखर के लिए बन रहीं हैं चुनौती

लखनऊ। स्विट्ज़रलैंड से लौटने के बाद डॉ. रोहिणी घावरी ने यूपी में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। उनका फोकस वाल्मीकि समाज के बीच शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर है। पिछले तीन दिनों में मेरठ से लखनऊ तक समाज के लोगों के साथ बैठकें करने के बाद बुधवार को वह लवकुश नगर स्थित श्रीमती मुन्नी देवी वाल्मीकि स्मारक विद्यालय पहुंचीं। यहां बच्चों से संवाद करते हुए उन्होंने शिक्षा को समाज की तरक्की का आधार बताया।

रोहिणी की सक्रियता को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी की दलित राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। 15 सितंबर को लखनऊ में करणी सेना के कार्यक्रम में उन्हें झांसी की रानी की उपाधि देकर तलवार भेंट की गई थी। इसके

बाद उन्होंने करणी सेना अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू के साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। इस दौरान आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे पर चर्चा हुई। रोहिणी कह चुकी हैं कि वह खुद चुनाव लड़ने के बजाय वाल्मीकि समाज के लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए काम करेंगी। उनका कहना है कि जो दल आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने के साथ समाज को टिकट और संगठन में हिस्सेदारी देगा, वह उसके साथ जाएंगी। उनकी सक्रियता नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के प्रभाव क्षेत्र में भी देखी जा रही है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

उत्तर प्रदेश अब दंगा और कर्फ़्यू मुक्त है : योगी

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 119 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब दंगा और कर्फ़्यू मुक्त है तथा अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। इसके

अलावा यूपी कैबिनेट ने 300 करोड़ रुपये से 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 119 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अच्छे लोग चुने जाते हैं, तो नतीजे भी अच्छे ही मिलते हैं। कुछ महीने पहले इस इलाके में 1.5-2 मीटर चौड़ा गड्ढा था और चारों तरफ़ कचरा पड़ा रहता था। यहाँ गंदगी रही होगी, लेकिन अब यहाँ एक शानदार बाउंड्री बन गई है और उसके ऊपर यह भव्य कल्याण मंडपम बनकर तैयार हो गया है। जगह वही है, लेकिन सिर्फ़ लोगों के बदलने से देखिए कैसा बदलाव आता है।

करोड़ों उड़ाने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश

नई दिल्ली। पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ आईएफएसओ इकाई ने गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी से करोड़ों रुपये उड़ाने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ठगी की रकम 34 बैंक खातों में 317 बार स्थानांतरित की गई थी, जिसमें से 1.7 करोड़ रुपये पुलिस ने फ्रीज करा दिए हैं। जांच में सामने आया है कि ठगी की रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेश भेजा जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के कॉर्पोरेट बैंक खाते से डिजिटल माध्यम से 12.84 करोड़ रुपये निकालने में कथित तौर पर शामिल एक साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 317 बार में यह रकम डिजिटली स्थानांतरित की और इनमें एक बैंक का 'रिलेशनशिप मैनेजर' भी शामिल है।

पाकिस्तान-चीन सीमा आयोग पर भारत की कड़ी आपत्ति

नई दिल्ली । भारत ने पाकिस्तान और चीन के बीच बनाए गए तथाकथित सीमा संयुक्त आयोग को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने बुधवार को इस आयोग को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के बीच ऐसी कोई मान्य सीमा नहीं है, जिसे भारत स्वीकार करता हो। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि इस मामले में भारत की स्थिति पहले से स्पष्ट और लगातार एक जैसी रही है। मंत्रालय ने कहा कि तथाकथित संयुक्त आयोग का कोई कानूनी आधार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग से जुड़ी रिपोर्ट देखी है। भारत की स्थिति स्पष्ट है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई मान्य सीमा नहीं है। इसलिए भारत इस तथाकथित संयुक्त आयोग को स्वीकार नहीं करता। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस आयोग की कोई कानूनी वैधता नहीं है।

यूपी: चुनावी तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव

लखनऊ । सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि नकारात्मक अभियान भाजपा का हथियार है। भाजपा समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ डिजिटल अभियान चला रही है। भाजपा की भाषा अलोकतांत्रिक है। भाजपा का

एजेंडा समाज में नफरत फैलाना है। भाजपा लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण की विरोधी है। इस सरकार ने मुनाफाखोरी कर महंगाई बढ़ाई है। अखिलेश प्रदेश सपा मुख्यालय पर विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2027 में पीडीए के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पार्टी का नेता-कार्यकर्ता एकजुटता के साथ काम करें। समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी घोषित होगा, उसी का पूरा साथ देकर जिताकर विधायक बनाना है। सपा अखिलेश यादव ने कहा कि शाहजहांपुर में एक जर्जर स्कूल की बीम गिरने से एक शिक्षामित्र की मृत्यु होना बेहद दुखद है।

सेंसर बोर्ड का भारत सरकार ने किया पुनर्गठन, 18 सदस्य शामिल

भारत सरकार ने सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन किया। गठित किए गए नए बोर्ड में कुल 18 सदस्य हैं। इनमें अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी, मनोज जोशी,

प्रोसेंजीत चटर्जी, अभिनेत्री प्रीति जिंटा, रूपाली गांगुली और पल्लवी जोशी समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। पुनर्गठित सेंसर बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, अभिषेक जैन, रिकी केज, प्रियदर्शन, सुनील शेट्टी, हंसराज हंस, सुप्रिया यार्लगड्डु, यतींद्र मिश्रा, रूपाली गांगुली, प्रीति जिंटा, नीला माधब पांडा, पंकज त्रिपाठी, प्रोसेंजीत चटर्जी, पल्लवी जोशी, निशिगंधा वाड, वामन केंद्रे और रमेश पतांगे को शामिल किया गया है। इस बदलाव के बाद मुख्य रूप से सेंसर बोर्ड के सदस्यों में बदलाव हुआ है, जबकि बोर्ड की कानूनी भूमिका पहले जैसी ही रहेगी। सेंसर बोर्ड अभी भी सिनेमैटोग्राफ एक्ट और 2024 के फिल्म सर्टिफिकेशन नियमों के तहत काम करेगा। नए सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 साल का होगा।

सेवा संकल्प अभियान

नई पीढ़ी को नरेंद्र मोदी से मिले उड़ान के लिए पंख

पी.वी. सिंधु

क्या होता अगर दस साल पहले कोई भारतीय युवा लड़की कहती कि उसे रॉकेट बनाना है। उसे इसरो में शामिल होकर नहीं, बल्कि अपना खुद का रॉकेट बनाना है। ऐसी स्थिति में शायद उसके आसपास के लोग खामोश रह जाते। फिर कोई बहुत सहानुभूति से उसे समझाता कि यह उसके बस की बात नहीं है। वह समझाता कीअंतरिक्ष पर सिर्फ सरकार का हक होता है। इतने बड़े सपने तो दूसरे देशों के लोगों के लिए होते हैं। 18 जुलाई, 2026 को एक प्राइवेट भारतीय कंपनी का बनाया रॉकेट अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंच गया। इस रॉकेट को स्काईरूट ने बनाया था, जिसकी बुनियाद दो नौजवान इंजीनियरों ने रखी थी। दोनों ने अपने सुरक्षित काम छोड़ कर इस लगभग नामुमकिन सपने को सच करने की ठान रखी थी। स्काईरूट की इस कामयाबी के साथ ही भारत दुनिया के उन सिर्फ तीन देशों में शामिल हो गया जहां किसी आम नागरिक की प्राइवेट कंपनी अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है। इस कामयाबी को हासिल करने वाले बाकी दो देश अमेरिका और चीन हैं। वह लड़की, जिसके सपने के पूरा होने का किसी को भी भरोसा नहीं था, अब कह सकती है-

''मैं एलन मस्क बनना चाहती हूं। यह कोई नारा नहीं, बल्कि मेरा पक्का इरादा है।'' बेशक, वह अपने सपने को पूरा करने की यात्रा को शुरू कर सकती है।

पिछले दस वर्षों में हमारे देश में प्रतिभाओं में कोई बदलाव नहीं आया है। भारत के पास काबिलियत हमेशा से थी। जो चीज़ बदली, वह था अवसर। हमारे इतिहास में ज्यादातर समय किसी बड़े सपने का जवाब यह होता था कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। इसलिए नहीं कि काबिलियत में कोई कमी थी। इसलिए कि मंजिल तक पहुंचने का दरवाजा ही बंद था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सबसे खामोश और सबसे बड़ी कामयाबी यह रही कि अब वह दरवाजा खुल चुका है।

इस बदलाव की गहराई को समझना

बहुत जरूरी है। दशकों तक भारत में हर बड़े सपने को रुकावटों का सामना करना पड़ता था। कोई भी अहम काम करने के लिए आपको लाइसेंस, मंजूरी, जान-पहचान या प्रभावशाली परिवार के नाम की जरूरत पड़ती थी। देश में सपने देखने वालों की कभी कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ दरवाजों की। और जब दरवाज़े कम हों तो वे सबसे पहले उनके लिए खुलते हैं जिनके पास पहले से चाबियां होती हैं। नौजवान, गरीब और वे लोग दरवाज़े के बाहर ही इंतज़ार करते रह जाते थे जिनके पास कोई बड़ी पहचान नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बंद दरवाजे को देखा और समझा कि असल में इसके क्या कारण थे। उन्होंने इस बदलाव को एक ही लाइन में बयान किया- सरकार का रवैया 'जब तक इजाज़त न हो, तब तक पाबंदी' से बदल कर 'जब तक मना न हो, तब तक इजाज़त' हो गया है। उनके पूरे दशक के काम के पीछे एक पक्का संकल्प रहा है- पाबंदियों की इस दीवार को और उसकी जगह खुले दरवाज़ों वाला देश बनाना। ऐसा देश जहां इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसकी संतान हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या बनाने की काबिलियत रखते हैं।

जरा गौर करें कि क्या-क्या खुल गया है। अंतरिक्ष पर 60 साल तक सरकार का एकाधिकार रहा। 2020 में उसे उन सबके लिए खोल दिया गया जिनके पास रॉकेट छोड़ने की योग्यता थी। फिर हमारे खेतों के ऊपर का आसमान खुला। उस रूल बुक को फाड़ कर फेंक दिया गया जिसके मुताबिक एक छोटे से ड्रोन को उड़ाने के लिए दर्जनों कागज़ात और इजाज़तों की ज़रूरत पड़ती थी। अब किसी छोटे शहर का कोई नौजवान अपना ड्रोन बना सकता है। उसे फोन के जरिए रजिस्टर कर अपना कारोबार शुरू कर सकता है। गांवों की हज़ारों महिलाओं के हाथों में ड्रोन सौंप दिए गए जिससे भविष्य का एक हिस्सा उनकी आजीविका का जरिया बन गया। इनमें से कुछ बदलाव बहुत दबे पांव आए लेकिन उनकी अहमियत उतनी ही ज्यादा थी। 2021 में मानचित्रों को मुक्त कर दिया ताकि किसी भारतीय कंपनी को उस देश का सर्वे करने के लिए किसी मंजूरी की ज़रूरत नहीं पड़े जिसमें वह पहले से काम कर रही है।

खेलो छत्तीसगढ़ • बढ़ो छत्तीसगढ़

खेलों से बदलती तस्वीर

नया छत्तीसगढ़, नए अवसर और नई पहचान

— खेल मैदानों से निकल रही नई ऊर्जा, युवाओं के सपनों को मिल रही नई उड़ान —

छत्तीसगढ़ आज केवल अपनी प्राकृतिक संपदा, संस्कृति और परंपराओं के लिए ही नहीं, बल्कि खेलों के क्षेत्र में उभरती नई पहचान के लिए भी देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों और योजनाओं ने खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाकर हजारों युवाओं के जीवन में नई उम्मीद जगाई है। खेल अब केवल मनोरंजन या प्रतियोगिता का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह आत्मविश्वास, रोजगार, सामाजिक परिवर्तन और प्रदेश की नई पहचान का आधार बन चुका है। राज्य के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों से लेकर शहरों तक खेलों का ऐसा वातावरण निर्मित हुआ है, जहां प्रतिभाओं को अवसर मिल रहे हैं और युवाओं के सपनों को पंख लग रहे हैं। खेल अवसंरचना का विस्तार, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं, खेल अकादमियों की स्थापना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पारंपरिक खेलों का संरक्षण—इन सभी प्रयासों ने छत्तीसगढ़ को खेल विकास के एक नए मॉडल के रूप में स्थापित किया है।

मुख्यमंत्री का संदेश

“ हमारी सरकार का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ का प्रत्येक युवा अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर प्राप्त करे। खेल केवल प्रतियोगिता का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निर्माण का सशक्त आधार है। इसी सोच के साथ हम गांवों, वनांचलों और दूरस्थ क्षेत्रों तक खेल सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, खेल अकादमियों और युवा कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों युवाओं को नई दिशा मिली है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ”

-विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

बस्तर बना खेल क्रांति का नया केंद्र

कभी चुनौतियों और संघर्षों के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर आज खेल प्रतिभाओं की नई धरती के रूप में उभर रहा है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित बस्तर ओलंपिक ने इस परिवर्तन को नई दिशा दी है। गांव-गांव और जंगलों के बीच बसे इलाकों से हजारों युवा खेल मैदानों तक पहुंचे हैं। खेलों के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक मंच मिला है और उनके भीतर छिपी प्रतिभाओं को पहचान मिली है। फुटबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल और अन्य खेलों में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर यह साबित किया है कि अवसर मिलने पर बस्तर की प्रतिभाएं किसी से कम नहीं हैं। इस पहल ने सामाजिक समरसता को भी मजबूत किया है।

आधुनिक खेल अकादमियां गढ़ रहीं भविष्य के चैंपियन

प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आधुनिक खेल अकादमियों का नेटवर्क लगातार मजबूत किया गया है। बस्तर क्षेत्र में शुरू हुई आवासीय खेल अकादमी ने आदिवासी और ग्रामीण अंचलों के युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। इन अकादमियों में खिलाड़ियों को आवास, भोजन, खेल सामग्री, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और अनुभवी प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। तीरंदाजी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी और अन्य खेलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवा अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।

सरगुजा ओलंपिक : खेल प्रतिभाओं को उड़ान देने का छत्तीसगढ़ मॉडल

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित सरगुजा ओलंपिक 2025-26 युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के इस आयोजन में एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कराटे और तीरंदाजी सहित 12 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। जूनियर और सीनियर वर्ग के खिलाड़ी विकासखंड, जिला एवं संभाग स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीयन व्यवस्था से अधिकाधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण-पत्र, शील्ड, मोमेंटो और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और नई प्रतिभाओं को मंच देने का प्रभावी माध्यम बन रहा है।

खिलाड़ियों के सम्मान में खुला प्रोत्साहन का नया अध्याय

राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए देश की अग्रणी पुरस्कार नीतियों में से एक को लागू किया है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिलने से खेलों के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ा है। अब खेल को केवल शौक नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक करियर के रूप में भी देखा जाने लगा है। हजारों युवा खेलों के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।

सामाजिक समरसता को मिली नई मजबूती

खेलों के जरिए सशक्त हो रहा नया छत्तीसगढ़

आज छत्तीसगढ़ में खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, युवा सशक्तीकरण और समावेशी विकास का प्रभावी साधन बन चुका है। खेल मैदानों में दौड़ते युवा, तीरंदाजी के लक्ष्य भेदते खिलाड़ी, हॉकी और फुटबॉल के उभरते सितारे तथा पारंपरिक खेलों में भाग लेते ग्रामीण जन—ये सभी एक विकसित और आत्मविश्वासी छत्तीसगढ़ की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। राज्य सरकार की खेलोन्मुखी नीतियों और निरंतर प्रयासों ने प्रदेश को नई पहचान दी है। आने वाले वर्षों में यही युवा शक्ति छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और अधिक मजबूत स्थान दिलाएगी।

मुख्यमंत्री खेल उत्कृष्टता मिशन से नई संभावनाएं

प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को प्रारंभिक स्तर से पहचानकर उन्हें उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री खेल उत्कृष्टता मिशन एक महत्वपूर्ण पहल बनकर सामने आया है। इस मिशन के अंतर्गत खेल अवसंरचना, प्रशिक्षण सुविधाओं, कोचिंग व्यवस्था और प्रतियोगिताओं के आयोजन पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों से प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना है।

राष्ट्रीय मंच पर चमक रही छत्तीसगढ़ की प्रतिभाएं

आज छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। प्रदेश के युवा धावकों, तीरंदाजों, हॉकी खिलाड़ियों और अन्य खेल प्रतिभाओं ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित कर राज्य का गौरव बढ़ाया है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से निकलकर राष्ट्रीय टीमों तक पहुंचने वाले खिलाड़ियों की सफलता यह दर्शाती है कि सही दिशा, बेहतर प्रशिक्षण और मजबूत सरकारी सहयोग मिलने पर छत्तीसगढ़ की प्रतिभाएं वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकती हैं।

छत्तीसगढ़ ने झारखंड को हराकर महिला फुटबॉल में जीता गोल्ड

खेलो इंडिया और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मजबूत उपस्थिति

राज्य की खेल अकादमियों और प्रशिक्षण केंद्रों से तैयार हुए खिलाड़ियों ने विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। खेलो इंडिया जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों में प्रदेश के खिलाड़ियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आदिवासी अंचलों से आने वाले युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। यह सफलता राज्य सरकार की खेल नीति और दीर्घकालिक योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

डिजिटल व्यवस्था से बढ़ी पारदर्शिता

खेल प्रशासन में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। खिलाड़ियों के प्रमाण-पत्रों और उपलब्धियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, जिससे सत्यापन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को खेल विज्ञान, पोषण और एंटी-डोपिंग संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे खिलाड़ियों को सुरक्षित और पेशेवर वातावरण प्राप्त हो रहा है।

विश्वस्तरीय खेल अधोसंरचना गढ़ता छत्तीसगढ़

नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम छत्तीसगढ़ सरकार की दूरदर्शी खेल नीति का उत्कृष्ट उदाहरण है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह स्टेडियम राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मानचित्र पर नई पहचान दिला रहा है। यहां आयोजित बड़े टूर्नामेंटों ने प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, जबकि युवाओं को विश्वस्तरीय खेल वातावरण उपलब्ध कराकर छत्तीसगढ़ को उभरते खेल केंद्र के रूप में स्थापित किया है।

खेल अकादमियां

बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, नारायणपुर सहित अनेक स्थानों पर आधुनिक खेल अकादमियां संचालित खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं।

बस्तर ओलंपिक

दूरस्थ वनांचल के हजारों युवाओं को मिला मंच, नक्सल हिंसा से प्रभावित एवं आत्मसमर्पित युवाओं की सहभागिता से सामाजिक समरसता को मिली नई मजबूती।

राष्ट्रीय उपलब्धियां

छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया, नई ऊंचाईयों को छुआ।

युवा सशक्तीकरण

युवा महोत्सव, नेतृत्व विकास, सामाजिक जागरुकता और फिटनेस कार्यक्रमों से हजारों युवाओं को सकारात्मक दिशा और नई पहचान।

संवाद-48873/2

“ खेलों की ताकत से आगे बढ़ता छत्तीसगढ़ — अवसर, सम्मान और उपलब्धियों का नया अध्याय ”

खेल एवं युवा कल्याण विभाग

संक्षिप्त समाचार

जीएसटी विभाग में 42 वाणिज्यिक कर निरीक्षक की नियुक्ति रद्द

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जीएसटी विभाग में वाणिज्यिक कर निरीक्षक बनने वाले 42 कर्मचारियों को अब अपने पुराने पद पर लौटना होगा। इन कर्मचारियों को 2021 और 2022 में हुई सीमित भर्ती परीक्षा के जरिए लिपिक पद से वाणिज्यिक कर निरीक्षक बनाया गया था। बाद में इस भर्ती परीक्षा को लेकर शिकायतें सामने आईं। इसके बाद जांच कराई गई। जांच में परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने वाली कई गड़बडियां मिलीं। चयनित कर्मचारियों की कॉपियों में एक जैसे जवाब पाए गए। कुछ मामलों में दोबारा जांच के बाद अंक बढने की बात भी सामने आई। वहीं, परीक्षा में कौन-कौन कर्मचारी शामिल हुए थे, इसका उपस्थिति रिकॉर्ड भी नहीं मिला। जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य कर आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने परीक्षा और उसके आधार पर हुए चयन को रद्द कर दिया। इसके साथ ही 42 कर्मचारियों को वाणिज्यिक कर निरीक्षक पद से हटाकर उनके मूल लिपिक पद पर वापस भेजने का आदेश जारी किया है।

एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम के दूसरे राउंड की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मेडिकल और डेंटल कालेजों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अपडेट सामने आया है। एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के दूसरे राउंड की प्रवेश प्रक्रिया बुधवार से आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। शिक्षा संचालनालय ने दूसरे राउंड की सीट आवंटन सूची जारी कर दी है, जिससे छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। विद्यार्थियों को अब 16 से 22 सितंबर तक अपने आवंटित कॉलेज में जाकर प्रवेश की सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इस चरण में कुल 2099 विद्यार्थियों को सीटें आवंटित की गई हैं। इनमें से 1084 विद्यार्थियों को पहली बार सीट मिली है, जबकि 1015 विद्यार्थियों ने अपने कॉलेज या कोर्स को अपग्रेड करने के लिए आवेदन किया था। हालांकि, इनमें से केवल 239 विद्यार्थियों का ही अपग्रेडेशन सफल हो सका है। शेष 776 विद्यार्थियों को पहले से आवंटित कॉलेज या पाठ्यक्रम में ही संतुष्ट होकर प्रवेश लेना होगा। इस बार की प्रवेश प्रक्रिया में एक दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिला है, जहां सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तुलना में निजी मेडिकल कॉलेजों की मैनेजमेंट सीटों का कटऑफ अधिक रहा है। मैनेजमेंट कोटे में अधिकतम 549 नीट स्कोर तक प्रवेश मिला है, जबकि नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में यह आंकड़ा 511 स्कोर तक सीमित रहा। इसके अलावा, एनआरआई कोटे के तहत भी निजी कॉलेजों में सीटें लगातार आवंटित की जा रही हैं।

धमतरी और बालोद जिलों में 5 सिंचाई योजनाओं के लिए 21.50 करोड़ स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा किसानों को बड़ी राहत देते हुए धमतरी और बालोद जिलों की पांच प्रमुख सिंचाई योजनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्यों के लिए कुल 21 करोड़ 50 लाख 23 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन योजनाओं के पूर्ण होने से क्षेत्रीय किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। धमतरी जिला के राजाडेरा लघु जलाशय जलद्वार के नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्य के लिए 1 करोड़ 65 लाख 7 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे लगभग 285 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसी प्रकार खट्टी एनीकट (महानदी) महानदी पर निर्मित खट्टी एनीकट के संरक्षण और जलद्वारों के उन्नयन कार्य हेतु 4 करोड़ 89 लाख 30 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे करीब 30 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। बालोद जिला (कुल 3 योजनाएं) के जलाशयों में विद्युतीकरण तांदुला, गोंदली और खरखरा जलाशय में विद्युतीकरण व प्रकाश व्यवस्था के कार्यों के लिए 4 करोड़ 95 लाख 99 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे 285 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।

रावतपुरा फेस-2 के 40 मकानों पर चला निगम का बुलडोजर

रायपुर। बुधवार की सुबह नगर निगम का अमला बड़ी संख्या में बुलडोजरों के साथ रावतपुरा फेस-2 कॉलोनी पहुंचा, जहां नियमों के विपरीत बनाए गए मकानों पर तोडफ़ोड़ की कार्रवाई की गई। इस दौरान निगम अधिकारियों के साथ पुलिस बल भी मौके पर मौजूद थे। रावतपुरा फेस-2 कॉलोनी में नगर निगम की ओर से करीब 40 मकान मालिकों को नोटिस जारी किया गया था। इन मकानों का निर्माण स्वीकृत नक्शे के बिना कराया गया है। नोटिस जारी होने के बाद कार्रवाई की स्थिति बनने पर निगम की टीम बुधवार को मौके पर एक दर्जन बुलडोजर के साथ पहुंची और चलाने की कार्रवाई शुरु की। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई थी।

राज्य प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों का तबादला

रायपुर। राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक नये जगहों पर पदस्थ किया है। जिनमें मनीष मिश्रा (रा.प्र.से.) उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) से स्कूल शिक्षा विभाग, उप सचिव श्री भागवत जायसवाल (रा.प्र.से.) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं श्री गुड्डू लाल जगत (रा.प्र.से.) उप सचिव श्रम विभाग से आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग में भेजे गए है। उक्त आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनराखन भूआर्य के हस्ताक्षर से जारी हुआ।

विश्वकर्मा जयंती पर होगा भव्य श्रमिक महासम्मेलन, मुख्यमंत्री होंगे मुख्य अतिथि

सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में होगा आयोजन

रायपुर। भगवान विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर 17 सितंबर को राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया जाएगा। श्रमिकों के सम्मान, उनके योगदान को रेखांकित करने और श्रम शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से आयोजित इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर (आबकारी) एवं श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन करेंगे।

सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा, रायपुर में दोपहर 12 बजे से आयोजित होने वाला यह महासम्मेलन प्रदेश के श्रमवीरों के सम्मान का महत्वपूर्ण अवसर होगा। निर्माण से लेकर उद्योग, कृषि, सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में अपने परिश्रम से प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले श्रमिक इस आयोजन के केंद्र में रहेंगे। भगवान विश्वकर्मा जयंती श्रम, कौशल,

निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक है। इस अवसर पर आयोजित श्रमिक महासम्मेलन के माध्यम से श्रम के सम्मान और श्रमिकों के महत्व का संदेश प्रदेशभर में पहुंचाया जाएगा। श्रमिकों की मेहनत और कौशल से ही विकास की मजबूत नींव तैयार होती है। छत्तीसगढ़ के विकास में श्रम शक्ति की इसी महत्वपूर्ण भूमिका को यह आयोजन रेखांकित करेगा।

कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और मंत्री केदार कश्यप विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इनके साथ मंत्री रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, श्याम बिहारी जायसवाल, ओ.पी. चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, गजेन्द्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब, राजेश मूणत, मोतीलाल साहू, पुंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, इंद्र कुमार साहू, डॉ. रामप्रताप सिंह, योगेश दत्त मिश्रा और किशोर महानंद सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। महासम्मेलन में महापौर श्रीमती मीनल चौबे तथा जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल की भी सहभागिता रहेगी।

विश्वकर्मा जयंती के इस विशेष अवसर पर आयोजित श्रमिक महासम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि प्रदेश के श्रमवीरों के परिश्रम, कौशल और छत्तीसगढ़ के विकास में उनके अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का सार्वजनिक अभिव्यक्तिकरण होगा।

नवा रायपुर में 32वें अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का शुभारंभ

■ राज्यपाल ने किया ईयर बुक का विमोचन

रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर में 32वें अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। लगभग 11 वर्षों के अंतराल के बाद छत्तीसगढ़ को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी मिली है। सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने किया।

शुभारंभ समारोह पर राज्यपाल डेका ने 'Chhattisgarh Local Body Election Year Book–2026' के प्रथम संस्करण का विमोचन भी किया। यह प्रकाशन छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया, उपलब्धियों, नवाचारों और चुनावी व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश करता है।

उद्घाटन सत्र को राज्यपाल रमेन डेका ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सशक्त, पारदर्शी, समावेशी और तकनीक-सक्षम बनाने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके निर्वाचन की प्रक्रिया में निरंतर सुधार और आधुनिक तकनीक का उपयोग जरूरी है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने देशभर से आए राज्य निर्वाचन आयुक्तों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं निर्वाचन विशेषज्ञों का स्वागत किया गया। उन्होंने सम्मेलन के उद्देश्यों को लेकर जानकारी दी। साथ ही स्थानीय निकाय निर्वाचन को अधिक प्रभावी एवं आधुनिक बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी बताया। वहीं छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव विकास शील ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने, प्रशासन और निर्वाचन संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय को लेकर विचार रखे।

सम्मेलन के दौरान स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनावों से जुड़े विषयों, डिजिटल पहलों, तकनीकी नवाचारों के साथ कई उपायों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन के प्रथम दिन डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग, निर्वाचन प्रबंधन में नवाचार, पारदर्शिता जैसे विषयों पर परिचर्चा की शुरुआत हुई। दो दिवसीय यह सम्मेलन देश में स्थानीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने, राज्यों के अनुभवों और नवाचारों को साझा करने का मंच दे रहा है। 17 सितम्बर को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय नवा रायपुर अटल नगर में स्टैंडिंग कमिटी की बैठक होनी है।

पीएम आवास पर सियासत

कांग्रेस कार्यकाल में गरीबों के साथ हुआ अन्याय: रामविचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास के मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। पूर्व सीएम बघेल और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के बीच सीधी और तीखी बहस में उनके अपने-अपने दावों से राजनीति का पारा हाई है। इस बीच मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर निशाना साधा है।

मंत्री रामविचार नेताम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में पीएम आवास का काम रोककर रखा था। सभी को मालूम है कि कांग्रेस सरकार में गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में गरीबों से पक्के आवास का वादा किया था, जिसे सरकार में आने के बाद पूरा भी किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने भी घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ में जहां आवास की जरूरत होगी वहां उपलब्ध कराया जाएगा।

एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) को सेवा संकल्प अभियान के जरिए

भाजपा भव्य आयोजन करने जा रही है। वहीं दूसरे तरफ कांग्रेस ने महंगाई दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मंत्री नेताम पर कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम से कांग्रेस के कपड़े गीले हो जाते हैं।

उन्होंने बताया कि देशभर में प्रधानमंत्री मोदी के सेवा सुशासन का 25 वर्ष पूरा होने जा रहा है। पीएम मोदी के जन्मदिन को उत्साह के साथ विभिन्न कार्यक्रम करते हुए मनाया जाएगा। वह भी आशीर्वाद का दिया जलाकर दीर्घायु की कामना करेंगे। पीएम मोदी ने देश के लिए जो किया वो सभी के लिए प्रेरणादायक है। ऐसा प्रधानमंत्री पाकर देश गर्व महसूस कर रहा है।

भूपेश सरकार में हुआ संवैधानिक अधिकारों का हनन : डॉ. मिश्रा

जीएसटी इंस्पेक्टर पदोन्नति में घोटाला: युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली भूपेश सरकार बेनकाब

रायपुर। कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार के कार्यकाल में युवाओं के हकों पर डाका डालने और अपनों को उपकृत करने के एक और सनसनीखेज मामले के खुलासे के मद्देनजर तीखा हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने कहा है कि भूपेश सरकार के संरक्षण में राज्य के प्रतिभावान युवाओं और कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मिश्रा ने बुधवार को यहाँ एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता में बताया कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में जाँच के दौरान भारी धांधली, फर्जीवाड़ा और प्रणालीगत भ्रष्टाचार पाया गया है। इसके बाद शासन द्वारा इस परीक्षा को तत्काल प्रभाव से शून्य घोषित कर पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि 26 जून 2022 को लिपिक वर्ग से वाणिज्यिक कर निरीक्षक (टैक्स इंस्पेक्टर) के पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। जाँच समिति की रिपोर्ट (3 जुलाई 2026) ने यह साफ कर दिया है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल मे किस प्रकार नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं!

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मिश्रा ने बताया कि परीक्षा से पहले आरक्षण रोस्टर का पालन ही नहीं किया गया, जिससे वंचित और पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों पर सीधी चोट पहुँचाई गयी। इसी तरह परीक्षा केंद्रों में उपस्थिति पंजी का

संधारण ही नहीं किया गया ताकि मनचाहे लोगों की बैकडेट में एंट्री कराई जा सके। जाँच में पाया गया कि कई चयनित अभ्यर्थियों ने एक समान उत्तर लिखे थे। इतना ही नहीं, कॉपियों में कोडिंग व्यवस्था को जानबूझकर खत्म किया गया ताकि मनपसंद अभ्यर्थियों की पहचान उजागर रहे।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मिश्रा ने कहा कि अपनों को फायदा पहुँचाने के लिए चयन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों और परीक्षा नियंत्रक ने खुद नियम विरुद्ध पुनर्मूल्यांकन कर चहेतों के अंक बढ़ाए। खरीदी गई कॉपियों और इस्तेमाल/शेष कॉपियों के आँकड़ों में भारी विसंगतियाँ पाई गईं, जो सीधे तौर पर फर्जी कॉपियाँ जमा करने की ओर इशारा करती हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि जाँच में यह साबित हो चुका है कि भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुई यह परीक्षा पूरी तरह दूषित और फर्जीवाड़े पर आधारित थी। अनियमितताएँ इतनी व्यापक थीं कि इसमें से ईमानदार और धांधली करने वालों को अलग करना सम्भव नहीं था। शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए 26 जून 2022 की परीक्षा एवं 1 जुलाई 2022 के तहत दिए गए सभी नियुक्ति आदेशों को तत्काल निरस्त कर दिया है। फर्जी तरीके से टैक्स इंस्पेक्टर बने सभी कर्मचारियों को उनके मूल पदों पर वापस भेज (प्रत्यावर्तित कर) दिया गया है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मिश्रा ने कहा कि युवाओं और कर्मचारियों की मेहनत पर पानी फेरने वाली भूपेश सरकार को इस धांधली का जवाब देना ही होगा। क्या कांग्रेस सरकार का मकसद केवल अपनों को पिछले दरवाजे से लाभ पहुँचाना था?

डॉ. मिश्रा ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार का यह कृत्य न केवल प्रशासनिक मर्यादाओं का हनन था, बल्कि राज्य के परिश्रमी कर्मचारियों और युवाओं के विश्वास पर कुठाराघात था। अब सच सामने आ चुका है और धांधली के बल पर पाई गई नियुक्तियों को खारिज कर न्याय स्थापित किया गया है।

झीरम कांड: मुख्य दोषी तक नहीं पहुंच पाई एनआईए- धनेंद्र साहू

रायपुर। झीरम नक्सली हमला मामले में बुधवार को दोषियों को सजा सुनाई। इस मामले में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि स्थिति दुर्भाग्यजनक है। प्रदेश में जघन्य हत्याकांड हुए 13-14 वर्ष बीतने के बाद भी एनआईए मुख्य दोषी तक नहीं पहुंच पाई। जिन्हें अपराधी घोषित किया गया है वे वास्तविक अपराधी नहीं हैं। जिन लोगों को सजा मिल रही है वे सब नौकर-चाकर और कर्मचारी वर्ग के लोग हैं। मोस्टवांटेड लोगों को तो सजा ही नहीं मिली, वास्तविक हत्यारे तक जांच एजेंसी नहीं पहुंच पाई।

हल्दी बीज वितरण में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू ने कहा, चाहे किसी भी प्रकार के बीज हो, छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा नकली बीज के विक्रय का केंद्र बना है। हल्दी के बीज भी अमानक पाए गए हैं। जितने सहकारी सेवा केंद्र हैं उनमें भी अमानक स्तर के बीज निकल रहे

हैं। सरकार किसानों को अच्छे खाद-बीज का वितरण नहीं कर पा रही।

आंबेडकर अस्पताल में चूहा मारने पर 25 लाख खर्च, इस मामले में धनेंद्र साहू ने कहा, भाजपा को हर चीज में भ्रष्टाचार करना है। चूहों से डॉक्टर और मरीज सभी परेशान हैं। 25 लाख रुपये चूहे मारने के लिए दिए हैं, कितने चूहे मारे गए? क्या उसका भी पोस्टमार्टम करवाएंगे? भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे दवाई खरीदी में हो या किसी और मामले में, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है।

नगरीय निकाय चुनाव को लेकर धनेंद्र साहू ने कहा, जब से भाजपा की सरकार है तब से विकास कार्य ठप है। कहीं विकास कार्यों के लिए धनराशि नहीं है। अब शहरी क्षेत्रों में विकास कार्य करने की बात कही जा रही है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पर है। भाजपा के लोगों को हराने के लिए जनता पूरी तरह तैयार बैठी है। विकास कार्यों की स्थिति, महंगाई, बिजली, स्मार्ट मीटर, नालियां भरना और सफाई नहीं होने जैसे मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और चुनाव में कांग्रेस को जीत प्राप्त होगी। पीएम आवास पर बहस को लेकर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा, छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएम आवास को लेकर पूर्व सीएम और वर्तमान डिप्टी सीएम के बीच सार्थक चर्चा हुई। सरकार की ओर से जो फर्जी आंकड़े दिए जाते रहे, उसकी सच्चाई सामने आई। पोस्टर और कार्टून के माध्यम से भाजपा अपनी गलतियां छिपाने में लगी है। सभी पात्र हितग्राहियों को पीएम आवास का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, सरकार को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। जो खामियां है उन्हें दूर करना चाहिए। पीएम आवास को लेकर काफी लोगों को परेशानी है। कुछ लोग कर्ज में डूबे हैं।

संत ज्ञानेश्वर स्कूल के नचिकेत ने राज्य फेंसिंग स्पर्धा में जीता गोल्ड

रायपुर। महाराष्ट्र मंडल के संत ज्ञानेश्वर विद्यालय के नचिकेत तांडी ने छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शालेय फेंसिंग प्रतियोगिता में दो गोल्ड मेडल जीता है। बलौदाबाजार जिले के कसडोल में हुई शालेय फेंसिंग स्पर्धा में नचिकेत ने सेबर एकल इवेंट और सेबर टीम इवेंट में अपने प्रतिद्वंद्वियों को परास्त करके दो केटेगरी में विजेता होने का गौरव हासिल किया है।

महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले, उपाध्यक्ष गीता दलाल, सचिव चेतन गोविंद दंडवते सहित समस्त कार्यकारिणी, प्राचार्य मनीष गोवर्धन ने टीचर स्टाफ सहित नचिकेत को फेंसिंग स्पर्धा में मिली इस सफलता को शाला और महाराष्ट्र मंडल के लिए बड़ी उपलब्धिपूर्ण बताया। उन्हें सभी ने फेंसिंग स्पर्धा में अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने और भारत देश का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां भी कामयाबी के झंडे गाडने का आशीर्वाद दिया।

आशीर्वाद का दीया पर कांग्रेस का हमला, चूल्हे बुझ रहे, सरकार दीये जलाने में जुटी

■ तेल खर्च और खरीदी पर भी सवाल

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी सेवा संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान में कई तरह के आयोजन होंगे। इसी के तहत 17 सितंबर की शाम प्रदेशभर में आशीर्वाद का दीया जलाने की तैयारी है। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि चूल्हे बुझ रहे और सरकार दीये जलाने में जुटी है। इसके साथ ही दीये-तेल की खरीदी पर भी सवाल उठाए।

दरअसल, सरकार की ओर से इसे सेवा, सुशासन, जनभागीदारी और विकसित भारत के संकल्प से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकारी स्तर पर स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, शासकीय भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, पीडीएस दुकानों सहित अलग-अलग स्थानों पर दीप प्रज्वलन की तैयारियां की जा रही हैं। इस आयोजन को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने सरकार और भाजपा पर सवालों की बौछार कर दी है।

विकास उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा आयोजन देश की मौजूदा समस्याओं और आम जनता की जरूरतों से जुड़ा हो तो उसका संदेश अलग होगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के लिए रोजगार का रोडमैप तैयार किया जाता और महंगाई रोकने का संकल्प लिया जाता, तो इसे सार्थक पहल माना जाता।

उपाध्याय ने आरोप लगाया कि दीप जलाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके मुताबिक मितानिनों, शिक्षकों, सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों और नगर निगम के कर्मचारियों-अधिकारियों तक की ड्यूटी दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में लगाई गई है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब बड़े पैमाने पर दीप जलाने के लिए हजारों लीटर तेल की

जरूरत होगी, तो इसकी खरीदी किस माध्यम से की जा रही है। क्या इसके लिए टेंडर जारी किया गया है। क्या यह सरकारी आयोजन है और क्या इसके लिए बाकायदा सरकारी नोटशीट जारी हुई है?

विकास उपाध्याय ने कहा कि 25 लाख से ज्यादा दीप जलाने की बात कही जा रही है। ऐसे में तेल और अन्य सामग्री की खरीदी पर होने वाले खर्च तथा उसकी प्रक्रिया सार्वजनिक होनी चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि इस आयोजन में कमीशनखोरी हो सकती है और भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।

उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 25 साल पूरे होने जैसे अवसर को जनता के लिए उपयोगी योजनाओं और राहत से जोड़ा जा सकता था। पूर्व में भी नेताओं और प्रधानमंत्रियों ने अपने जन्मदिन या विशेष अवसरों पर लोगों को सौगात देने और जरूरतमंदों की मदद करने की पहल की है। विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि भाजपा महिमामंडन करने का प्रयास कर रही है। जब आम आदमी महंगाई और रोजगार जैसी समस्याओं से जूझ रहा हो, तब बड़े पैमाने पर दीप जलाने के आयोजन की प्राथमिकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

कांग्रेस के सवाल?

- 25 लाख से अधिक दीपों के लिए तेल की खरीदी कौन करेगा?
- खरीदी के लिए क्या टेंडर या निविदा प्रक्रिया अपनाई गई है?
- क्या यह सरकारी आयोजन है?क्या आयोजन के लिए सरकारी नोटशीट जारी की गई है?
- सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी किस आदेश के तहत लगाई गई है?
- आयोजन पर होने वाले खर्च का स्रोत और पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर के जन्मदिन और सार्वजनिक जीवन में उनके 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर भाजपा ने देशभर में सेवा संकल्प अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसी अभियान के तहत आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम रखा गया है। इसके अंतर्गत 17 सितंबर की शाम लोगों से घरों में दीप जलाने की अपील की गई है।

छत्तीसगढ़ में इस आयोजन को बड़े स्तर पर करने की तैयारी है। राजधानी रायपुर में 25 लाख दीये जलाने का कार्यक्रम प्रस्तावित बताया गया है। यह आयोजन 17 सितंबर की शाम रायपुर के मरीन ड्राइव क्षेत्र में होगा और प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन तथा सुरक्षा समेत तैयारियां शुरू की हैं।

जब विपक्ष ने मुद्दों की जगह मीनू चुन लिया

डॉ. नीलम महेंद्र

ब्रिक्स की मेज पर दुनिया बैठी थी लेकिन विपक्ष की नजर थाली पर थी। भारत में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के आधिकारिक रात्रिभोज में विदेशी मेहमानों को शाकाहारी भारतीय व्यंजन परोसे गए। खांडवी, मशरूम गलौटी, पनीर लबाबदार, गुच्छी मार्मिक, बाजरे का पुलाव, बीटरूट रायता और पारंपरिक भारतीय मिठाइयों से सजा यह मेन्यू भारत की समृद्ध शाकाहारी पाक-परंपरा का प्रदर्शन था। लेकिन मेहमानों की मेज से उठकर यह मेन्यू सीधे भारतीय राजनीति की मेज पर पहुंच गया। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब भारत में अधिकांश लोग मांसाहारी हैं, तो विदेशी मेहमानों के सामने केवल शाकाहारी व्यंजन क्यों परोसे गए। राहुल गांधी की ओर से 80 प्रतिशत भारतीयों के मांसाहारी होने का दावा भी सामने आया और सरकार पर खान-पान की पसंद थोपने का आरोप लगाया गया। अब प्रश्न यह नहीं है कि किसी को शाकाहारी भोजन पसंद है या नहीं। प्रश्न यह है कि न तो ब्रिक्स का मंच कोई पारिवारिक डिनर का मंच है और न ही राजकीय भोज का उद्देश्य यह साबित करना होता है कि देश के कितने प्रतिशत लोग क्या खाते हैं। यदि भारत किसी अंतरराष्ट्रीय आयोजन में अपने श्रेष्ठ शाकाहारी व्यंजनों को दुनिया के सामने रखता है, तो इसमें अस्वाभाविक क्या है? क्या किसी देश का सांस्कृतिक परिचय उसके पूरे मेन्यू कार्ड से ही तय होगा? खाने के मीनू पर भी राजनीति होगी! ब्रिक्स जैसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में क्या विपक्ष के पास सरकार से पूछने के लिए इससे बड़ा कोई प्रश्न नहीं था? दुर्भागपूर्ण है कि विपक्ष की नजर में ब्रिक्स की मेज पर असली मुद्दे क्या थे इससे अधिक महत्वपूर्ण खाने का मीनू है? सत्य तो यह है कि ब्रिक्स दुनिया की बदलती आर्थिक और रणनीतिक व्यवस्था में तेजी से महत्वपूर्ण होता हुआ मंच है। इसकी मेज पर व्यापार है, निवेश है, ऊर्जा है, तकनीक है, वित्तीय सहयोग है और बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका है। यानी विपक्ष के पास सवालों की कोई कमी नहीं थी। वह पूछ सकता था कि भारत ब्रिक्स के माध्यम से अपने आर्थिक हितों को किस तरह आगे बढ़ा रहा है? चीन के साथ व्यापार असंतुलन को लेकर भारत की रणनीति क्या है? ब्रिक्स के विस्तार से भारत की सामरिक स्थिति मजबूत होगी या जटिल? क्या भारत वैश्विक दक्षिण का प्रभावी नेतृत्व कर पा रहा है? स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और डॉलर पर निर्भरता कम करने की चर्चा का भारत के लिए क्या अर्थ है? ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी सहयोग में भारत को क्या अवसर मिल सकते हैं? ब्रिक्स में भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन कैसे साध रहा है? ये वे प्रश्न थे जिन पर सरकार को असहज किया जा सकता था। ये वे प्रश्न थे जिन पर विपक्ष अपनी विदेश नीति की समझ दिखा सकता था। ये वे प्रश्न थे जिनसे जनता को पता चलता कि विपक्ष सत्ता का गंभीर विकल्प बनने की तैयारी कर रहा है। लेकिन विपक्ष ने चुना क्या मेन्यू! यहीं से यह विवाद केवल भोजन का विवाद नहीं रह जाता। यह राजनीतिक प्राथमिकता का प्रश्न बन जाता है। यह विपक्ष की राजनैतिक प्राथमिकताओं पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है। क्या एक राजकीय भोज जनगणना होता है? विपक्ष का तर्क है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग मांसाहारी हैं। तो क्या राजकीय भोज का मेन्यू जनगणना के आंकड़ों के अनुपात में तय होता है? यदि देश में 70 प्रतिशत लोग किसी विशेष भोजन को पसंद करते हैं तो क्या मेन्यू में 70 प्रतिशत वही भोजन होना चाहिए? यदि किसी राज्य में मांसाहार प्रमुख भोजन है तो क्या हर अंतरराष्ट्रीय भोज में मांसाहार अनिवार्य होनी चाहिए?

जन्मदिन विशेष

मोदी होना आसान नहीं

सुरेश हिंदुस्तानी

कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं बनता, उसके द्वारा किए गए कर्म ही उसकी छवि बनाते हैं। भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म से सब प्राप्त किया जा सकता है। गुजरात के निर्धन परिवार में जन्म लेने वाले नरेंद्र मोदी के व्यापक विस्तार की कहानी भी ऐसी ही है। मोदी ने अपने और अपने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा। उनके चिंतन के केंद्र में आम आदमी प्रमुखता से है। संभवत: वे पंडित दीनदयाल जी की उस उक्ति को धरती पर लाने का उपक्रम कर रहे हैं, जिसमें अंतिम छोर पर निवास करने वाले व्यक्ति का उत्थान छुपा हुआ है। तभी तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है। इतना ही नहीं, वे अपने आपको प्रधान सेवक मानने में गौरव का अनुभव करते हैं। उन्होंने जनता के साथ जुड़ाव बनाने वाला यह कथन अपने जीवन में समाहित कर लिया है। ऐसा जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी होना आसान नहीं है।

किसी व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होने वाला पद बड़ा हो सकता है, लेकिन पद से बड़ा होता है उसका व्यक्तित्व। कुर्सी शक्ति दे सकती है, किंतु उस शक्ति को धैर्य, संयम और संकल्प के साथ साधना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व इसी कारण अलग दिखाई देता है। उनके समर्थकों के लिए वे संघर्ष से निकली उस यात्रा के प्रतीक हैं, जिसमें अभावों से उठकर व्यक्ति देश के सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंचता है। सच कहें तो मोदी होना आसान नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वर्तमान राजनीतिक चुनौतियां नई नहीं हैं। सत्ता के गलियारों में जितनी प्रशंसा मिलती है, उतनी ही तीखी आलोचना भी उनका पीछा करती है। राजनीतिक प्रहारों की निरंतरता किसी भी व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले सकती है। लेकिन मोदी की राजनीतिक शैली की एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि वे अपने समर्थकों की अपेक्षाओं और विरोधियों के आक्रोश के बीच अपना संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। राजनीति में विरोध आवश्यक है। लोकतंत्र में सत्ता से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। नीतियों की सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक असहमति जब व्यक्तिगत कटुता का रूप लेती है, तब लोकतंत्र की गरिमा प्रभावित होती है। ऐसे वातावरण में भी स्वयं को संयमित रखना किसी नेता के लिए सामान्य बात नहीं।

आज की राजनीति केवल मोदी का समर्थन या विरोध पर ही केंद्रित हो गई है। इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि मोदी का प्रचार विपक्षी दलों ने अधिक किया है।

मोदी की राजनीतिक यात्रा का सबसे प्रेरक पक्ष उनका संघर्ष है। एक सामान्य परिवार से निकलकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की कहानी भारतीय लोकतंत्र की उस शक्ति को रेखांकित करती है, जिसमें किसी व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि उसकी अंतिम सीमा तय नहीं करती। अभावों में पला व्यक्ति भी अपने परिश्रम, अनुशासन और संकल्प के बल पर राष्ट्र के नेतृत्व तक पहुंच सकता है। यही मोदी की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। संघर्ष व्यक्ति को तोड़ता नहीं, यदि उसके भीतर संकल्प जीवित हो तो वही संघर्ष उसे गढ़ता है।

मोदी के व्यक्तित्व की चर्चा करते समय उनके परिवार और व्यक्तिगत जीवन का पक्ष भी सामने आता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका परिवार सत्ता के केंद्र में दिखाई नहीं देता। सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए पारिवारिक जीवन को राजनीतिक लाभ से दूर रखने की उनकी छवि उनके समर्थकों के लिए विशेष महत्व रखती है। भारतीय राजनीति में जहां परिवारवाद लंबे समय से बहस का विषय रहा है, वहां मोदी की व्यक्तिगत राजनीतिक यात्रा एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करती है।

मोदी की कहानी केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। आज विश्व मंच पर भारत की उपस्थिति पहले से अधिक प्रभावशाली दिखाई देती है। अनेक देशों के साथ भारत के संबंधों का विस्तार हुआ है। वैश्विक मंचों पर भारत की शक्तिशाली भूमिका को लेकर चर्चा बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की आवाज को गंभीरता से सुना जाना उस बदलते भारत का संकेत है, जो अपनी क्षमता, अपने हितों और अपनी सभ्यता की पहचान के साथ विश्व समुदाय के सामने खड़ा होना चाहते हैं। वे जब विदेश दौरा करते हैं, तब वे भारतीय मूल के नागरिकों से अवश्य मिलते हैं। इस दौरान भारतीय मूल के व्यक्तियों के चेहरे बहुत ही प्रफुल्लित दिखाई देते हैं। वे सभी मोदी को एक सफल नायक की श्रेणी में देखते हैं। अपनेपन का यह भाव मोदी के स्वभाव का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए विदेश यात्राओं या कूटनीतिक मुलाकातों का विषय नहीं है। यह उस आत्मविश्वास का विषय है, जिसके साथ भारत आज विश्व समुदाय से संवाद कर रहा है।

एक समय था जब दुनिया के अनेक शक्तिशाली देश भारत को मुख्यत: एक विकासशील राष्ट्र के रूप में देखते थे। आज भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी युवा शक्ति, उसकी तकनीकी क्षमता, उसका विशाल बाजार और उसकी सामरिक भूमिका विश्व की चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परिवर्तन का पूरा श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना उचित नहीं होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने भारत की इस वैश्विक प्रस्तुति को निश्चित रूप से एक विशिष्ट राजनीतिक दिशा दी है। और यही मोदी की विशेषता का एक महत्वपूर्ण आयाम है। वे भारत को केवल वर्तमान के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य की संभावना के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व जितना मुखर है, उतना ही व्यक्तिगत जीवन में सादगी और अनुशासन की छवि से जुड़ा हुआ भी है। सार्वजनिक जीवन में निरंतर सक्रियता, दैनिक रूप से लंबे कार्य घंटे, देश-विदेश की यात्राएं और करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं का भार, प्रधानमंत्री का जीवन किसी सामान्य नौकरी की तरह नहीं होता। प्रत्येक निर्णय के पीछे राजनीतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय परिणाम जुड़े होते हैं।

और इसीलिए प्रधानमंत्री होना केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है। यह हर दिन स्वयं को कटघरे में खड़ा करना भी है। एक ओर समर्थकों की अपेक्षाएं, दूसरी ओर विरोधियों के सवाल। एक ओर देश की आकांक्षाएं, दूसरी ओर विश्व की निगाहें। एक ओर वर्तमान की चुनौतियां, दूसरी ओर भविष्य के भारत की जिम्मेदारी। इन सबके बीच संतुलन बनाना ही नेतृत्व की वास्तविक परीक्षा है।

नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके जीवन को देखने का सबसे सार्थक तरीका यही है कि हम उनके संघर्ष, संकल्प और नेतृत्व की यात्रा को समझें। मतभेद लोकतंत्र की सुंदरता हैं। उनके भीतर एक ऐसा नेतृत्व दिखाई देता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता। उनके आलोचक चाहे उनके निर्णयों से सहमत हों या नहीं, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि नरेंद्र मोदी आज भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली और चर्चित चेहरों में से एक हैं। उनकी यात्रा हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि ऊंचाई पर पहुंचना कठिन है, लेकिन उस ऊंचाई पर टिके रहकर निरंतर आगे बढ़ते रहना उससे भी कठिन है।

मोदी होना इसलिए आसान नहीं है। मोदी होने के निहितार्थ यही हैं संघर्ष को शक्ति में बदलना। आलोचना को सहने का धैर्य रखना। सफलता के बीच जमीन से जुड़े रहना। भारत की आकांक्षाओं को विश्व के सामने आत्मविश्वास से रखना। और सबसे बढ़कर, स्वयं से बड़ी किसी राष्ट्रीय आकांक्षा के लिए निरंतर काम करते रहना।

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें देखने का एक दृष्टिकोण यह भी है कि एक साधारण पृष्ठभूमि से निकला व्यक्ति किस प्रकार भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में असाधारण राजनीतिक पहचान बना सकता है। राजनीति के निर्णयों का मूल्यांकन इतिहास करेगा। नीतियों की समीक्षा समय करेगा। उपलब्धियों और कमियों का आकलन आने वाली पीढ़ियां करेंगी। लेकिन संघर्ष की कहानी अपनी जगह रहती है। और नरेंद्र मोदी की कहानी का यही सबसे बड़ा भाव है, एक साधारण शुरुआत से असाधारण शिखर तक की यात्रा। इसलिए जन्मदिन के इस अवसर पर एक वाक्य सहज ही मन में उभरता है कि मोदी होना आसान नहीं।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

3-यज्ञ-प्रक्रिया के क्षेत्र में दर्शन शास्त्र का विकास

गतांक से आगे...

यज्ञ के द्वारा स्वर्ग और अनेक उच्च लोकों की प्राप्ति बताई गई थी, और उन स्वर्गादि लोकों में अनेक प्रकार के भोग साधन प्राप्त करना ही यज्ञ का उद्देश्य था। यह स्पष्ट है कि उपनिषदों का ब्रह्मवाद और उस पर आश्रित वाह्य-जगत् की असत्यता यज्ञ-सम्बन्धी कर्मकाण्ड की जड़ को हिलाने वाली थी।

यज्ञ की सफलता और कर्मकाण्ड-सम्बन्धी विश्वास की दृढ़ता के लिए यह आवश्यक था कि बाह्य जगत् की यथार्थता स्थापित की जाए। बाह्य जगन् की यथार्थता दार्शनिक रूप से सिद्ध करने के लिए यज्ञ-प्रक्रिया के क्षेत्र में या पूर्वमीमांसा दर्शन के क्षेत्र में क्या कोई प्रयत्न किया गया, यह विचारणीय है।

यह विदित है कि प्राचीनकाल में अनेक प्रकार के विज्ञानों का उद्गम यज्ञ-प्रक्रिया के क्षेत्र में हुआ था। यज्ञ में उच्चारण की शुद्धि के लिये शिक्षा विज्ञान का प्रारम्भ हुआ, यज्ञ-सम्बन्धी वाक्यों के परिवर्तन करने में कोई अशुद्धि न हो, इसके लिए व्याकरण विज्ञान का जन्म हुआ।

यज्ञ की तिथि को पहले से ठोक ठोक निवय करने के लिए ज्योतिष का प्रारम्भ हुआ, यज्ञ की वेदी को नापकर ठोक ठोक बनाने को दृष्टि से शुल्व सूत्रों में रेखा-गणित के प्रारम्भिक सिद्धान्त स्थापित किये गये, यज्ञ प्रक्रिया के सहायक इन अनेक विज्ञानों के साथ क्या यह आवश्यक न था कि बाह्य जगत् का यथार्थ स्वरूप स्थापित करने के लिये कोई दार्शनिक प्रक्रिया स्थापित की जाए?

ऊपर कहा गया है कि न्याय और वैशेषिक शास्त्र का उपनिषदों के सिद्धान्तों या ब्राह्मणों के कर्म काण्ड से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं।

परन्तु वे वैदिक दर्शन कहलाते हैं। वेदों से उनका सम्बन्ध किस प्रकार है, यह एक प्रश्न है।

क्रमश: ...

विश्वकर्मा पूजा

अंकुर अग्निहोत्री

हिंदू धर्म में विश्वकर्मा पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है, जो भगवान विश्वकर्मा को समर्पित त्योहार है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों में उन्हें वास्तुकला, शिल्पकार, निर्माण और तकनीकी कौशल से जुड़ा हुआ देवता माना जाता है।

भारत वर्ष में विश्वकर्मा भगवान की पूजा मुख्य रूप से कारीगरों, इंजीनियरों, मैकेनिकों, फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों, बिल्डरों, तकनीशियनों और व्यापारियों द्वारा अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। हर साल की ही तरह इस वर्ष भी विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। भारत के ज्यादातर लोगों के मन में विश्वकर्मा पूजा को लेकर एक सवाल उठता है कि, क्या इस दिन घर पर पूजा की जा सकती है?

हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा के लिए कोई कठोर नियम नहीं बताए गए हैं, इसलिए आप घर पर भी श्रद्धा भाव और विधि-विधान के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर सकते हैं। हालांकि यह त्योहार मुख्य रूप कारखानों, ऑफिसों और फैक्ट्री पर मनाई जाती है।

विश्वकर्मा पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि अपने कार्य, औजारों और तकनीकी साधनों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर भी है। इस दिन कार्यस्थल की साफ-सफाई करके भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है।

मान्यता के अनुसार भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से कार्य में कुशलता, सफलता और सकारात्मकता प्राप्त होती है।

कन्या संक्रांति के दिन ही विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष कन्या संक्रांति का शुभ समय करीब 7 बजकर 58 मिनट पर मनाया जाएगा। अलग-अलग शहरों में पूजा करने के लिए शुभ समय शहर और स्थानीय पंचांग के आधार पर अलग हो सकता है। इसलिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से पहले अपने क्षेत्र के पंचांग में बताए गए शुभ मुहूर्त का ही पालन करें।

विश्वकर्मा पूजा विधि जानिए

- विश्वकर्मा पूजा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ वस्त्र पहनें।
- इसके बाद कार्यस्थल, कारखाने, ऑफिस, मशीनें और औजारों को अच्छी तरह से साफ कर लें।
- चारों और गंगाजल से छिड़काव कर वातावरण को शुद्ध करें।
- विश्वकर्मा भगवान को फूलों की माला, ताजे पुष्प आदि अर्पित करें और भगवान को अक्षत, रोली आदि भी अर्पित करें।
- भगवान विश्वकर्मा की पूजा के लिए चित्र स्थापित करें और विधिवत रूप से उनकी पूजा-अर्चना करें।

भगवान विश्वकर्मा से जुड़ा मंत्र

भगवान विश्वकर्मा को प्रसन्न करने के लिए इस दिन अपनी भक्ति में उनसे जुड़ा एक खास मंत्र ऊं विश्वकर्मणे नम: जरूर शामिल करें।

2029 से पहले 21 राज्यों में लागू होगा यूसीसी

नीरज कुमार दुबे

समान नागरिक संहिता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद देश की राजनीति में जैसे भूचाल-सा आ गया है लेकिन हंगामा कर रहे लोगों को समझना चाहिए कि यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) का विचार आज की राजनीतिक बहस की उपज नहीं है। संविधान निर्माताओं ने ही इसकी कल्पना की थी और संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को पूरे देश में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया। संविधान सभा में डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने भी स्पष्ट किया था कि विवाह और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को समान नागरिक कानून के दायरे में लाने की संवैधानिक मंशा है। यानी यूसीसी संविधान की मूल बहस का हिस्सा था, कोई अचानक सामने आया राजनीतिक एजेंडा नहीं। इसके बावजूद आजादी के बाद लंबे समय तक वोट बैंक की राजनीति और तुष्टिकरण की नीति के चलते कांग्रेस तथा उसके समर्थन वाली सरकारें विभिन्न समुदायों के निजी कानूनों को छूने से बचती रहीं। मगर नरेंद्र मोदी सरकार इस मुद्दे पर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ताजा बयान इस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मुंबई में अमित शाह ने कहा कि 2029 से पहले भाजपा-एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तीन तलाक खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में कदम उठाया गया है और कई राज्यों में यूसीसी की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। शाह का संदेश साफ है कि मोदी सरकार यूसीसी को केवल चुनावी घोषणा बनाकर छोड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि राज्य सरकारों के जरिए इसे विस्तार देने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है।

उधर, अमित शाह के इस ऐलान के साथ ही विपक्ष ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में देर नहीं की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि

किसी भी विचारधारा को संविधान से ऊपर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने उत्तराखंड और दूसरे राज्यों में लागू या प्रस्तावित यूसीसी को उच्च न्यायपालिका की कसौटी पर परखे जाने की बात कही और कहा कि मौलिक अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता जैसे सवालों पर अंतिम निर्णय अदालतों को करना होगा। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इससे भी आगे बढ़कर सवाल किया कि यूसीसी से बेरोजगारी, महंगाई या पेट्रोल-डीजल की कीमतों जैसी आर्थिक समस्याएं कैसे दूर होंगी। उनका आरोप है कि सरकार इस मुद्दे के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाने की राजनीति कर रही है।

देखा जाये तो यहीं से यूसीसी की असली राजनीतिक लड़ाई सामने आती है। एक पक्ष इसे समानता, लैंगिक न्याय और एक समान नागरिक अधिकारों की दिशा में संवैधानिक कदम बता रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों से जोड़कर देख रहा है। लेकिन राजनीतिक आरोपों से अलग इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यूसीसी का संवैधानिक आधार मौजूद है और व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों और केंद्र दोनों के पास है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आते हैं। इसलिए केवल संसद से केंद्रीय कानून की प्रतीक्षा करने की बजाय राज्य भी अपने-अपने स्तर पर कानून बना सकते हैं।

सबसे अहम बात यह है कि अब यूसीसी को लेकर बहस केवल राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं है। मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के उन प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि यूसीसी का समय आ गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने यह भी संकेत दिया था कि अगर मुस्लिम उत्तराधिकार कानून के किसी प्रावधान को रद्द कर दिया गया तो वैधानिक व्यवस्था में खालीपन पैदा हो सकता है। अदालत ने यह सवाल भी उठाया था कि ऐसे व्यापक बदलाव का रास्ता न्यायपालिका की बजाय विधायिका के माध्यम से क्यों न निकले। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी की संवैधानिक बहस को नकारा नहीं, बल्कि व्यापक कानून बनाने की जिम्मेदारी विधायिका की ओर इंगित की।

यही नहीं, विधि आयोग का रिकॉर्ड भी इस बहस को एकतरफा नहीं रहने देता। 21वें विधि आयोग ने 2018 में 'Reforms of Family Law' परामर्श पत्र जारी किया था। बाद में 22वें विधि आयोग ने जून 2023 में यूसीसी पर नए सिरे से जनता, धार्मिक संगठनों और दूसरे हितधारकों से सुझाव मांगे। सरकार के अनुसार 21वें आयोग ने अंतिम रिपोर्ट नहीं दी और 22वां आयोग भी यूसीसी पर अपनी रिपोर्ट पूरी नहीं कर सका। इस तरह यह मामला व्यापक परामर्श और विधायी विकल्पों की पड़ताल की प्रक्रिया में रहा है।

अब सवाल यह है कि यूसीसी वास्तव में जमीन पर कैसा दिखता है? उत्तराखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 27 जनवरी 2025 से वहां यूसीसी लागू है और विवाह, तलाक, भरण-पोषण तथा उत्तराधिकार जैसे मामलों के लिए धर्म के आधार पर अलग-अलग व्यवस्था के स्थान पर एक समान ढांचा लागू किया गया है। राज्य का आधिकारिक यूसीसी पोर्टल लगातार विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और अन्य सेवाओं के पंजीकरण के आंकड़े उपलब्ध करा रहा है। यानी यह केवल कागज पर बना कानून नहीं है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के स्तर पर काम कर रहा है।

इसके बाद गुजरात ने मार्च 2026 में यूसीसी विधेयक पारित किया। करीब आठ घंटे की बहस और विपक्ष के विरोध के बीच पारित इस कानून का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन-रिलेशनशिप से जुड़े मामलों के लिए समान कानूनी ढांचा तैयार करना है। इसके बाद मई 2026 में असम विधानसभा ने भी यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। असम का कानून बहुविवाह पर रोक, विवाह और लिव-इन-रिलेशनशिप के पंजीकरण तथा उत्तराधिकार में समानता जैसे प्रावधानों पर केंद्रित है। अनुसूचित जनजातियों को उनकी संवैधानिक और प्रथागत व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

गोवा का उदाहरण भी इस बहस में अक्सर निर्णायक रूप से सामने आता है। वहां ऐतिहासिक रूप से पुर्तगाली सिविल कोड से विकसित एक साझा नागरिक कानून व्यवस्था लंबे समय से मौजूद है। इसलिए भारत में यह दावा भी टिकता नहीं कि अलग-अलग समुदायों के लिए समान नागरिक कानून लागू करना अपने आप में असंभव या प्रशासनिक रूप से अव्यावहारिक है। या फिर यह किसी तरह का भेदभाव करता है। नएस्थान तलाशें

इसलिए अमित शाह के 2029 वाले ऐलान को सिर्फ एक चुनावी नारे के रूप में देखना ठीक नहीं होगा। उत्तराखंड में कानून लागू हो चुका है, गुजरात और असम विधायी रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं और गोवा का अपना ऐतिहासिक अनुभव मौजूद है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी की आवश्यकता पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और विधि आयोग ने भी इस विषय पर व्यापक परामर्श की प्रक्रिया चलाई है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ती है। राज्यों से शुरुआत हो चुकी है इसलिए देखना होगा कि क्या केंद्रीय स्तर पर भी इस संबंध में कोई कानून आता है या नहीं?

आज का इतिहास

1630 अमेरिका के बॉस्टन शहर की स्थापना।
1761 कोसाब्रोमा का युद्ध लड़ा गया।
1948 हैदराबाद रियासत का भारत में विलय।
1949 दक्षिण भारतीय राजनीतिक दल द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (द्रमुक) की स्थापना।
1956 भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन।
1957 मलेशिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ।
1974 बंगलादेश, ग्रेनेडा और गिनी बिसाऊ संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल।
1982 भारत और सिलोन(श्रीलंका) के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया।
1995 चीन की राजधानी बीजिंग में ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत अंतिम चुनाव सम्पन्न।
1999 ओसामा बिन लादेन का भारत के विरुद्ध जेहाद का ऐलान।
2000 जाफना प्रायद्वीप का चवाक छेड़ी शहर लिट्टे से मुक्त।
2001 अमेरिका ने स्पष्ट किया कि कश्मीर पर पाक के साथ कोई सौदेबाजी नहीं।
2002 इराक ने संयुक्त राष्ट्र हथियार निरीक्षकों को बिना शर्त देश में आने की अनुमति दी।
2004 यूरोपीय संसद ने मालदीव पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया।
2006 हवाना में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का शिखर सम्मेलन शुरू।
2006 भारतीय वायु सेना की स्पेशल फ़ोर्स यूनिट गरुड़ कमांडो कांगो के शांति मिशन पर रवाना।
2006 गुटनिरपेक्ष देशों की दो दिवसीय शिखर बैठक हवाना में सम्पन्न।
2006 भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्यूबा के अस्वस्थ राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो से मुलाकात की।
2008 जहाजरानी राज्यमंत्री के. एच. मुनियप्पा ने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राष्ट्रीय संरक्षा पुरस्कार 2006 प्रदान किए।
2009 केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने 123 भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के नाम अपनी वेबसाइट पर जारी किए। दिल्ली की दो और बिहार की 18 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव सम्पन्न हुए।
2011 न्यूयॉर्क के जुकोट्टी पार्क में वॉल स्ट्रीट घेरो आंदोलन की शुरूआत।
2017 कोरिया ओपन सुपर सीरीज़ जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनीं पी.वी. सिंधु।
2020 लोकसभा ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री मोदी के सेवा व सुशासन के स्वर्णिम 25 वर्ष

सुरेश पचौरी

नये भारत के शिल्परकार श्री नरेन्द्र मोदी अपनी अनवरत जनसेवा व राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर, 2001 को शुरू हुई थी, जब उन्होंने 12 वर्ष 7 माह तक गुजरात के सफल मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम बार शपथ ली। तब से लेकर आज तक उन्होंने जनसेवा से राष्ट्रसेवा के मंत्र को जी कर दिखाया है और उनकी इस यात्रा की गति न धीमी हुई और न रू?की, बल्कि कीर्तिमान स्थाउपित करते हुये सतत् जारी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 सितम्बमर, 2026 को अपने जीवन के 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके जन्म दिवस पर 17 सितंबर से 17 अक्टूोबर तक सेवा संकल्पन अभियान प्रारंभ करने जा रही है, जब उनके सुशासन के 25 वर्ष पूरे होंगे। 12 वर्ष 7 माह तक गुजरात के मुख्यमंत्री और कमोबेश इतनी ही अवधि के उनके प्रधानमंत्रित्व् कार्यकाल पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्होंने जनसेवा का कीर्तिमान और प्रतिमान रच दिया। गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से गांव बड़नगर से शुरू हुई उनकी जीवन यात्रा में आए तमाम उतार-चढ़ाव के बीच लगन, निष्ठान, परिश्रम, त्या ग, दृढ़ इच्छोशक्ति और राष्ट्रकप्रेम के चलते वे भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष बन चुके हैं। वे आज सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं जाने-पहचाने जाते, वरन आज वे विश्वन के अग्रणी शीर्ष नेताओं में शुमार हो चुके हैं। श्री नरेन्द्र मोदी को 36 देशों ने अपने सर्वोच्चम सम्माशन से विभूषित किया है। वे ऐसे तपे-तपाए जननेता हैं, जिनमें कुंदन की कठोरता भी है और चंदन की शीतलता भी विद्यमान है। उनके चिंतन में राष्ट्ररू, राष्ट्रेबोध एवं राष्ट्रीहित सर्वोपरि है और इसी उदात्त भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने किशोरावस्थाी में अपना घर-द्वार छोड़कर जनसेवा की ओर जो कदम बढ़ाए, वे आज तक नहीं रुके।

उन्होंवने दशकों से लंबित फैसलों को पूरा किया - चाहे धारा 370 की समाप्ति हो, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो या सीमाओं की अभेद्य सुरक्षा हो। विज्ञान के क्षेत्र में चंद्रयान-3 की सफलता से लेकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत तक, उनके हर कदम ने भारत को सशक्त बनाया है। स्वच्छ भारत से जल जीवन मिशन तक, उज्जसवला योजना से आयुष्मान भारत तक, किसान सम्मान निधि से लखपति दीदियों की आत्मनिर्भरता तक - हर योजना का एक ही ध्येय रहा है कि सबका जीवन बेहतर हो, भारत समर्थ बने। ये 25 वर्ष सिर्फ सत्ता के नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के विश्वास और एक दूरदर्शी नेता के तप, त्याग और नेतृत्व की गाथा है। प्रधानमंत्री के रूप में विगत लगभग साढ़े बारह वर्षों के दौरान मोदी जी ने भारत को आत्मतनिर्भर बनाने के लिए उन कार्ययोजनाओं को अमली जामा पहनाया, जिसका भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया गया था। चाहे वह सामाजिक-आर्थिक बदलाव हों, चाहे प्राकृतिक संसाधनों, खनिजों, सांस्कृतिक धरोहरों आदि का संरक्षण हो या फिर देश के किसानों के कल्याण के लिए कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था हो, सब पर विशेष ध्यान दिया गया। मोदी जी के मार्गदर्शन में युवाओं में नवाचार और आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल स्किल इंडिया जैसी योजनाओं का सूत्रपात हुआ है। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में प्रगति की रफ्तार दिन-ब-दिन बढ़ती नज़र आ रही है। आम आदमी के जीवन में खुशहाली आई, समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन में सुधार आया, दुनिया में भारत के मान-सम्मान में वृद्धि हुई, पड़ोसी देश पाकिस्तान को ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान मुंह की खानी

पड़ी। श्री मोदी देश हित में इतने दृढ़प्रतिज्ञ हैं कि दुनिया की कोई ताकत आज तक उन्हें अपने सिद्धांतों से न तो डिगा सकी है और न ही झुका सकी है। उनका यह आत्मबल न सिर्फ करोड़ों भारतवासियों बल्कि विश्व के दीगर मुल्कों में रहने वाले भारतवासियों को संबल प्रदान करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हमारी जीडीपी वृद्धि दर भी 7.8त्न है। रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। देश विरोधियों और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति परिणाममूलक है।

प्रधानमंत्री ने सरकार की योजनाओं के केन्द्र बिन्दु में हमेशा 'आम आदमी' को रखा। इस सोच के साथ गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। मसलन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के करोड़ों परिवारों को पक्के घर दिए गये। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लाखों शौचालयों का खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कराया गया। उज्जवला योजना के माध्यम से गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान कर उनके स्वामस्ष्ये और गरिमा की रक्षा की गई। बेहतर स्वोस्ष्य् सुविधा के मद्देनजर आयुष्माचन भारत योजना शुरू की गई, जिससे लगभग 60 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्यर बीमा का सुरक्षा कवच मिला। जल जीवन मिशन से हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। आधारभूत संरचना की बात की जाये तो प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्र की रीढ़ मानते हुए इसमें भारी निवेश किया। सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और डिजिटलीकरण में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिल रही है। ग्रामीण भारत में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में मेट्रो और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं मूर्तरूप ले रही हैं।

कर्मयोगी श्री नरेन्द्र मोदी ने अपना जीवन सर्वे भवन्तुर सुखिनन् के भाव को चरितार्थ करते हुए राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। वे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वानस का संकल्प लेकर भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने में अहर्निश लगे हुए हैं। मोदी जी के नेतृत्वी वाली केन्द्रग सरकार का सिद्धांत है- रिफार्म, परफार्म एवं ट्रांसफॉर्म। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबिर 2014 को स्वपच्छत भारत अभियान की शुरुआत की गई। पिछले साढ़े 12 वर्षों में यह अभियान एक जन आंदोलन बन गया है। साथ ही उज्जूवला योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत करोड़ो लोग लाभान्वित हुये हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के सम्मीान, युवाओं के सामर्थ्यप, किसानों की समृद्धि व महिलाओं के सशक्तिकरण को राष्ट्र निर्माण का विशेष आधार बनाया। श्री मोदी ने अपने विजन में अन्नदाता किसान को सदैव अपनी प्राथमिकता में रखा। उन्होंने किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए अनेक योजनाओं का प्रावधान किया। उनकी सोच बहुत स्पष्ट है कि कृषि आजीविका का साधन मात्र न रहे, बल्कि यह लाभ का व्यवसाय बने। फिलहाल किसानों के सम्मान स्वरूप उन्हें दी जाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सालाना 6 हजार रूपये की सीधी सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन बहुत साफ़ है कि किसानों को उनकी पैदावार का सही दाम मिले। इस बाबत् फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में रिकार्ड बढ़ोत्तरी की। पीएम फसल बीमा योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएमआरकेवाई) से अन्न दाता लाभान्वित हो रहे हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, परम्परागत कृषि विकास योजनाओं जैसी जनहितैषी पहल से उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में रेल नेटवर्क का व्यापक ऐतिहासिक उपलब्धि सहित विस्तार हो रहा है।

महिला सशक्तिकरण मोदी सरकार के विकास एजेंडे का प्रमुख हिस्सा है। मातृवंदन योजना, नारी शक्ति वंदन और 33 प्रतिशत आरक्षण से महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद जगी है। केन्द् सरकार का लक्ष्यर तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का है, जिनमें से लगभग डेढ़ करोड़ लखपति दीदी अपना गरिमामय जीवन जी रही हैं। बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों का आत्मदसम्माान बढ़ा है। तीन तलाक कानून की समाप्ति से मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्वस वाली केन्द् सरकार ने देश में लगभग 2 लाख से अधिक आयुष्माान आरोग्यल मंदिर खोले हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने स्विदेशी वैक्सीरन के आविष्कार में प्रेरक भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना संकल्पव विरासत का, संरक्षण भी और विकास भी के परिणाम स्वषरूप अयोध्यो में रामलला की दिव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठौ सम्पन्न? हुई। काशी में बाबा विश्वानाथ कॉरिडोर, उज्जैरन में महाकाल लोक, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, बद्रीनाथ क्षेत्र का विकास, करतार साहब कॉरिडोर को खुलवाना, हेमकुण्डड साहब और गिरनार में रोपवे बनाना, नमामि गंगे योजना, तिरुवल्लीर में कल्चकरल सेन्टीर बनाना आदि उल्लेखनीय कार्यों से भारत आत्मैगौरव के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में निर्णायक शिकंजा

कातिलाल मांडोत

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। घाटी में आतंकवाद को केवल बंदूक उठाने वाले आतंकियों तक सीमित मानने के बजाय उनके पूरे सहयोगी तंत्र को निशाना बनाया जा रहा है। इसी रणनीति के तहत रविवार को काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के नेतृत्व में कुलगाम और शोपियां सहित कई इलाकों में संदिग्ध ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। शोपियां के नादिगाम क्षेत्र में दिवंगत गुलाम हसन गनी के बेटे इरफान अहमद गनी के मकान पर भी सुरक्षा एजेंसियों ने दबिश दी। इस कार्रवाई का उद्देश्य आतंकवाद से जुड़े संवेदनशील मामले की कड़ियों को जोड़ना और उसके पीछे सक्रिय नेटवर्क की पहचान करना बताया गया है। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई अब उस दौर से आगे बढ़ चुकी है, जिसमें केवल किसी हमले के बाद आतंकियों की तलाश की जाती थी। सुरक्षा एजेंसियां अब आतंकवाद की पूरी संरचना को समझकर उस पर एक साथ प्रहार कर रही हैं। आतंकवादियों को हथियार उपलब्ध कराने वालों से लेकर उन्हें सुरक्षित ठिकाना देने वालों, आर्थिक मदद पहुंचाने वालों और सीमा पार बैठे आकाओं के निर्देशों को जमीन पर लागू करने वाले स्थानीय सहयोगियों तक जांच का दायरा बढ़ाया गया है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर में तलाशी और गिरफ्तारी की कार्रवाई लगातार दिखाई दे रही है। शनिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी सीमा पार आतंकी साजिश के मामले में कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपोरा, बारामूला और सोपोर सहित दस स्थानों पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसियों के अनुसार इस मामले की कड़ियां पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आकाओं और घाटी में सक्रिय उनके स्थानीय सहयोगी तंत्र से जुड़ी हुई हैं। ये स्थानीय सहयोगी आतंकवादियों को घुसपैठ के बाद रसद, हथियार और दूसरी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने में भूमिका निभाते हैं। ऐसे नेटवर्क को समाप्त करना आतंकवाद के खिलाफ स्थायी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। आतंकवाद की चुनौती को समझने के लिए कश्मीर की भौगोलिक और सामरिक स्थिति को भी देखना होगा। जम्मू-कश्मीर लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का सामना करता आया है। नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास की संवेदनशील परिस्थितियों का फायदा उठाकर आतंकवादी संगठनों ने समय-समय पर घुसपैठ की कोशिश की है। सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों के लिए स्थानीय सहयोगी नेटवर्क किसी भी साजिश को जमीन पर उतारने का महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदा रणनीति में इन सहयोगियों की पहचान और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इस पूरे अभियान में स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। किसी भी आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए केवल केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर्याप्त नहीं होती। स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और जमीन पर उपलब्ध सूचनाओं का सही इस्तेमाल अभियान की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाता है। जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल से आतंकवादियों और उनके मददगारों तक पहुंचने में सुरक्षा एजेंसियों को सहायता मिल रही है।

तो अब शुभेंदु करेंगे गरबा मर्यादा की भी रक्षा?

तरुण विजय

जिस प्रकार शुद्ध हिंदू उत्सव गरबा में गैर हिंदुओं को शामिल करने की विकृत सेकुलर आवाजें उठने लगीं हैं उनको देखते हुए लगता है कि मुख्यत: गुजरात और महाराष्ट्र में होने वाले गरबा उत्सवों की मर्यादा रक्षा के लिए तेजस्वी हिंदू ध्वज वाहक एवं पश्चिम बंगाल के महानायक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सहायता मांगने का समय आ गया है .

अब सब हैं कि सेक्युलर तालिबानी आवाजों के विरुद्ध हिंदुओं को चाहिए कि अपना अंगद समान पैर जमाया जाए। बंगाल से सीख ली जाए, जहाँ तेजस्वी वीर हिंदू नायक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दुर्गा पूजा को उसकी मूल गरिमा लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे सीखकर गरबा को पतन से बचाया जाए। गरबा शक्ति की उपासना से जुड़ा पारंपरिक हिंदू पूजा-स्वरूप है। यह धनकुबेरों और हिंदू-भावना विहीन भीड़ के लिए मस्ती-मस्ती का कार्निवल नहीं है। गरबा कोई सेक्युलर मनोरंजन मेला नहीं है। यह माँ अम्बा की भक्ति का हिंदू प्रतीक है। जो माँ दुर्गा की पूजा नहीं करते, जो उनके सामने शीश नहीं झुकाते, उनको गरबा में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं। इसका मूल रूप और अर्थ हिंदू ब्रह्मांड-दृष्टि, प्रतीकों और दिव्य स्त्री-शक्ति की साधना से आता है।

गरबा शब्द संस्कृत शब्द गर्भ से निकला है। पारंपरिक रूप में नर्तक एक घेरे में गर्भ दीप—छेदों वाले मिट्टी के घड़े में जलते दीये—या देवी की मूर्ति के चारों ओर नृत्य अभ्यर्थना करते हैं। दीपक जीवन-शक्ति, शरीर के भीतर दिव्य उपस्थिति और देवी

की सृजन-शक्ति का प्रतीक है। वृत्ताकार गति हिंदू चिंतन में काल के चक्र—सृष्टि, स्थिति और प्रलय—को दर्शाती है। गरबा शरद नवरात्रि में होता है, अर्थात् दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित नौ रातों में। यह पर्व महिषासुर पर दुर्गा की विजय का स्मरण है, जैसा देवी माहात्म्य (मार्कंडेय पुराण) में वर्णित है। भक्त माँ की स्तुति के गीत (गर्बी) गाते हैं, ताली देते हैं और नृत्य को पूजा तथा कृतज्ञता का माध्यम बनाते हैं। पारंपरिक माहौल में स्थान पवित्र माना जाता है- प्राय: नंगे पाँव नाचते हैं, आरती होती है, और केंद्र में दीपक या मूर्ति ही मुख्य रहती है। नवरात्रि व्रत माँ भगवती की भक्ति का चिह्न है। गरबा और डांडिया रास (जहाँ डंडे देवी के आयुधों के प्रतीक हैं) गुजरात में इसी भक्ति की सामाजिक अभिव्यक्ति बने।

लोक-नृत्य के रूप में यह शादियों और अन्य अवसरों पर भी होता रहा है, पर इसका सबसे विस्तृत और मुख्य संदर्भ दुर्गा-पूजा का नवरात्रि चक्र ही है। क्योंकि यह रूप देवी और उनके प्रतीकों के इर्द-गिर्द बुना गया है, पारंपरिक हिंदू साधक और संगठन इसे श्रद्धा का कर्म मानते हैं, सेक्युलर-गैरहिंदू मनोरंजन नहीं। जो दुर्गा को दिव्य माता नहीं मानते, मूर्ति-पूजा और धर्मिक विश्वास को अस्वीकार करते हैं, वे इस अनुष्ठान के उद्देश्य से बाहर हैं। गरबा को सिर्फ फन मेला कहना उसे उसके धर्मिक अर्थ से काट देता है और पूजा-भक्ति को तमाशा बना देता है।

अन्य धर्मों के अनुष्ठानों से तुलना स्वाभाविक है। ईद की नमाज़ इस्लामी मज़हब के अनुसार निर्धारित है। गैर-मुसलमानों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे औपचारिक नमाज़ में मजहबी कर्तव्य के रूप में शामिल हों; वह स्थान और स्वरूप उन लोगों का है जो उस आस्था को स्वीकार करते हैं। अनेक परंपराओं में मूल उपासना-कर्म की सीमाएँ ऐसी ही हैं। नवरात्रि में गर्भ दीप या दुर्गा की मूर्ति के चारों ओर होने वाला गरबा उसी श्रेणी का आस्था-विशिष्ट कर्म है, राज्य द्वारा थोपा गया खुला सांस्कृतिक मेला नहीं। आज कई स्थानों पर गरबा अत्यधिक व्यावसायिक हो चुका है और हिंदू-भावना विहीन इवेंट मैनेजरों के हाथों विकृत हो रहा है। समय आ गया है कि अंगद समान हिंदू आस्था और मर्यादा का पैर जमाया जाए। बंगाल से सीख ली जाए, जहाँ तेजस्वी वीर हिंदू नायक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दुर्गा पूजा को उसकी मूल गरिमा लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे सीखकर गरबा को पतन से बचाया जाए।

यूनेस्को ने 2023 में गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। उसमें इसके हिंदू सामाजिक स्वरूप और शक्ति/स्त्री-ऊर्जा के वृत्त को बनाए रखते हुए लोगों को जोड़ने की क्षमता का उल्लेख है। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का कहना सही है कि यह देवी-पूजा का रूप है, इसलिए प्रवेश उन्हीं का हो जो इस आस्था को साझा करते हैं। गरबा स्थलों पर प्रवेश नियंत्रण और पहचान जाँच की माँग इसीलिए है। मिश्रित आयोजनों में तनाव, हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने, अपमान और उत्पीड़न की घटनाएँ सामने आई हैं। गैर-हिंदुओं द्वारा हिंदू देवताओं का मज़ाक उड़ाने और गरबा के बहाने हिंदू लड़कियों को छेड़ने की खबरें भी आती रही हैं।

हिंदुओं को समावेशिता का पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। भारत का संविधान हिंदू-बहुल समाज में बना। यह कानून के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता और प्रत्येक समुदाय को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार देता है। भारतीय संविधान हिंदू समावेशिता की अभिव्यक्ति है। गरबा सनातन धर्म की मर्यादा से बँधा है। हिंदू अपनी संवेदनाओं के अनुरूप प्रवेश की शर्तें रख सकते हैं। मंदिर, मठ और पारंपरिक संप्रदाय पहले से कुछ अनुष्ठान-स्थानों पर मर्यादा के अनुसार प्रवेश नियंत्रित करते हैं। दुर्गा-पूजा पर आधारित सामुदायिक गरबा पर भी वही तर्क लागू होना चाहिए।

अब साधु-संन्यासियों और पारंपरिक हिंदू स्वरों से अपील करनी चाहिए कि वे विशिष्ट हिंदू रूपों की मर्यादा स्पष्ट करें और उसकी रक्षा करें। ये माँगें धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुकूल हैं। शास्त्रीय नवरात्रि रूप में गरबा दुर्गा भगवती—माता और शक्ति के स्वरूप—के प्रति भक्ति का हिंदू अनुष्ठान है। गर्भ-दीप, वृत्ताकार गति, स्तुति-गीत तटस्थ मनोरंजन नहीं हैं। जो यह विश्वास नहीं रखते, वे इसके धार्मिक उद्देश्य से बाहर हैं, जैसे गैर-मुसलमान ईद की औपचारिक नमाज़ की संरचना से बाहर हैं।

यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का रास्ता साफ!

नीरज कुमार दुबे

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को अब वह बड़ा रणनीतिक समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, जिस पर लंबे समय से पूरी दुनिया की नजर थी। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतारेस की मौजूदगी में चीन और रूस ने भारत को संयुक्त राष्ट्र, विशेषकर सुरक्षा परिषद में बड़ी भूमिका देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराकर भारत के दावे को नई ताकत दे दी है। इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका भी सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन हर बार यह मामला चीन की असहमति पर आकर अटक जाता था। अब पहली बार ऐसा संकेत मिल रहा है कि चीन का रुख भी बदल रहा है। रूस के साथ चीन का समर्थन मिलना केवल भारत की कूटनीतिक जीत नहीं, बल्कि सुरक्षा परिषद की दशकों पुरानी शक्ति-संरचना के सामने एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक संदेश भी है।

इस घटनाक्रम को तमाम अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक भारत के लिए बड़ी जीत बता रहे हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेफ्री सैक्स ने तो यहां तक कहा है कि भारत के अलावा कोई दूसरा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के छठे स्थायी सदस्य बनने का इतना मजबूत दावा नहीं रखता। सैक्स ने भारत की करीब डेढ़ अरब की आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, वैश्विक प्रभाव और कूटनीतिक क्षमता को इसकी सबसे बड़ी ताकत बताया। उनका कहना है कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, क्रय शक्ति के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में लगातार अपनी प्रभावशाली भूमिका साबित कर रहा है।

हम आपको यह भी बता दें कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की नई दिल्ली घोषणा में चीन और रूस ने स्पष्ट रूप से भारत और ब्राजील की संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में बड़ी भूमिका निभाने की आकांक्षा के प्रति अपना समर्थन

दोहराया है। चीन का यह रुख खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह लंबे समय से भारत की स्थायी सदस्यता की मांग का खुलकर समर्थन करने से बचता रहा है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता रखने वाला चीन यदि भारत के दावे के समर्थन में खड़ा होता है, तो यह भारत के लिए बड़ी राहत की बात है।

उल्लेखनीय है कि सुरक्षा परिषद में फिलहाल पांच स्थायी सदस्य हैं। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। इनके पास वीटो पावर है, जिसके जरिये इनमें से कोई भी देश किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को रोक सकता है। इसके अलावा दस अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल दो वर्ष का होता है। इसके अलावा, विडंबना देखिए कि 1945 में जिस वैश्विक शक्ति-संतुलन को ध्यान में रखकर यह व्यवस्था बनाई गई थी, वही ढांचा आज भी लगभग उसी रूप में कायम है। जबकि दुनिया की आबादी, अर्थव्यवस्था, शक्ति-संतुलन और राजनीतिक वास्तविकताएं बदल गईं, लेकिन सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का ढांचा नहीं बदला।

यही वह बिंदु है जहां संयुक्त राष्ट्र सुधार की जरूरत सबसे ज्यादा दिखाई देती है। जिस संस्था का मूल उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना है, वही संस्था जब दुनिया के बड़े हिस्से को निर्णय प्रक्रिया से पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दे पाती, तो उसकी वैधता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की विशाल आबादी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का ढांचा बेहद असंतुलित है। देखा जाये तो दुनिया के संकटों का असर जिन देशों और समाजों पर सबसे ज्यादा पड़ता है, निर्णय लेने की मेज पर उनकी आवाज उतनी ही कमजोर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी असमानता को रेखांकित करते हुए वैश्विक निर्णय व्यवस्था को विशेषाधिकारों की पिरामिड जैसी संरचना बताया है। उन्होंने कहा कि ऊपर बैठे शक्तिशाली देश निर्णय लेते हैं और नीचे मौजूद देशों को उन निर्णयों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने इस विशेषाधिकार की पिरामिड को साझेदारी के मंच में बदलने का आह्वान किया है। उनका यह संदेश केवल ब्रिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था के सामने एक सीधी चुनौती है।

प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतारेस की मुलाकात में भी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और बहुपक्षीय संस्थाओं, विशेषकर सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने संघर्षों, समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता, सतत विकास, मानव-केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा और वैश्विक खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। यह अपने आप में संकेत है कि आज की वैश्विक समस्याएं इतनी व्यापक हो चुकी हैं कि उन्हें पुराने शक्ति-संतुलन और सीमित प्रतिनिधित्व वाली संस्थाओं के सहारे नहीं संभाला जा सकता।

देखा जाये तो भारत की स्थायी सदस्यता का सामरिक महत्व यहीं से सामने आता है। भारत केवल दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश नहीं है; वह एशिया की एक निर्णायक शक्ति, परमाणु शक्ति, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ की प्रमुख आवाज है। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान मिलने का अर्थ होगा एशिया और विकासशील दुनिया की निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक हिस्सेदारी बढ़ना। रणनीतिक स्तर पर चीन और रूस का समर्थन भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक पूंजी है। इससे यह धारणा कमजोर होती है कि भारत की स्थायी सदस्यता केवल पश्चिमी देशों की इच्छा पर निर्भर है। अब रूस और चीन जैसे स्थायी सदस्य भी इसके समर्थन में खुलकर खड़े दिखाई दे रहे हैं।

मेलोडी, ठेकुआ, मखाना-सत्तू— भारत की फूड डिप्लोमेसी का नया दौर

संजीव कुमार मिश्र

रोम वाला वो क्लिप शायद आपकी फीड पर भी घूमा होगा। पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को एक छोटा-सा टॉफी पैकेट थमाते हैं, और मेलोनी मुस्कुराते हुए बोल पड़ती हैं— "He gifted us a very, very good toffee" संयोग ऐसा कि टॉफी का नाम ही था मेलोडी! बस, इंटरनेट ने दोनों नामों को जोड़कर बना दिया मेलोडी, और वो मीठा पल रातोंरात एक मीम बन गया। एक साधारण-सी पार्ले टॉफी ने पूरे सोशल मीडिया पर राज कर लिया। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ इत्तेफाक समझ रहे हैं, तो थोड़ा रुकिए। भारत की विदेश नीति में डिप्लोमेसी की अपनी अहमियत है ही, मगर पिछले कुछ बरसों में खाना भी उसमें एक चुपचाप मगर मजबूत किरदार निभाने लगा है। खाना अब सिर्फ पेट भरने की चीज़ नहीं रहा — यह एक सोची-समझी सॉफ्ट पावर की चाल बन चुका है। जैसे भाषा, संगीत या सिनेमा किसी देश की पहचान गढ़ते हैं, वैसे ही अब थाली भी एक तरह की चुप कूटनीतिक ज़बान बोलने लगी है। एक टॉफी, एक मिठाई, या किसी गाला डिनर का मेन्यू— ये सिर्फ मेहमाननवाज़ी नहीं, बल्कि बहुत सोच-समझकर गढ़ा गया एक संदेश होता है। टाइमिंग पर गौर करें तो मई 2026 में पीएम मोदी की पांच देशों की यात्रा का आख़िरी पड़ाव इटली ही था। मेलोनी को मेलोडी टॉफी सौंपना महज एक हल्का-फुल्का पल नहीं था, इसके पीछे की टाइमिंग सोच-समझकर तय की गई लगती है। वीडियो वायरल होते ही वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया कि पिछले 12 वर्षों में भारत का टॉफी निर्यात 166% बढ़ चुका है। यानी एक मामूली-सा गिफ्ट भी सरकार ने आसानी से एक आर्थिक नैरेटिव में बदल दिया — देखिए, भारत की मिठास अब दुनिया के बाज़ार में बिक रही है। यही डिप्लोमेसी की असली चाल है— जो चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए, उसे आंकड़ों के सहारे एक आर्थिक कहानी में ढाल दो। यह सिर्फ एक तोहफा नहीं था — यह बिहार की सीधी-सादी सांस्कृतिक पहचान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिली एक तरह की इज़्ज़त थी। जो मिठाई कभी सिर्फ त्योहारों तक सीमित मानी जाती थी, वह अब भारत की कूटनीतिक पहचान का हिस्सा बन चुकी है। बारीकी से देखें तो यह कोई अचानक शुरू हुआ चलन नहीं है। 2023 में जब भारत ने जी20 की मेज़बानी की थी, तभी से इस रणनीति की झलक दिखनी शुरू हो गई थी। भारत मंडपम के उस गाला डिनर का पूरा मेन्यू वसुधैव कुटुंबकम यानी एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की थीम पर सजाया गया था। रागी डोसा, बाजरा खीर, कजू मटर मखाना से लेकर गोलगप्पे और समोसे तक — विदेशी मेहमानों को भारत के मिलेट्स और स्ट्रीट फूड, दोनों का ज़ायका एक साथ चखाया गया। यहीं से भारत ने खाने को महज़ मेहमाननवाज़ी नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक हथियार की तरह बरतना शुरू किया। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने इसे हर बिहारवासी के लिए गर्व का पल बताया, और बात भी सही है — जो मखाना और सत्तू कभी सिर्फ बिहार के गांव-देहात की रसोई तक सीमित थे, वे अब दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक मंचों में से एक तक पहुंच चुके हैं। यह बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और परंपरा, दोनों के लिए एक बड़ी वैश्विक पहचान है। मेलोडी टॉफी से लेकर मखाने तक — भारत की गिफ्ट और मेन्यू डिप्लोमेसी में एक साफ पैटर्न नज़र आता है।

कवर्धा मेडिकल कॉलेज का पहला बैच शुरू

35 विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश, उपमुख्यमंत्री ने किया स्वागत

कवर्धा। कबीरधाम जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। शासकीय मेडिकल कॉलेज में पहले बैच ने एडमिशन लिया है। 50 एमबीबीएस सीटों की क्षमता वाले मेडिकल कॉलेज में फिलहाल 35 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है।

प्रथम बैच के विद्यार्थियों का उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और सांसद संतोष पांडेय ने गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। इस दौरान दोनों ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। कवर्धा में शासकीय मेडिकल कॉलेज की शुरुआत के साथ जिले के विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा शिक्षा का नया रास्ता खुल गया है।

मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इस दौरान विद्यार्थियों को मेडिकल किट भी प्रदान की गई।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य केवल डॉक्टर बनना नहीं, बल्कि चिकित्सा के माध्यम से समाज और देश की सेवा करना भी होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया।

विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल सहित आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। आने वाले समय में कवर्धा मेडिकल कॉलेज प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाएगा।- विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री

सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि कवर्धा में मेडिकल कॉलेज का सपना अब साकार हो रहा है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए लोकसभा में कई बार आवाज उठाई और केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के भव्य भवन का निर्माण कार्य जारी है और भवन तैयार होने के बाद विद्यार्थियों की पढ़ाई नए परिसर में होगी।

बालोद के जंगलों में जड़ी बूटियों की खोज

औषधि साधक और बैगा जंगल से दुर्लभ जड़ी बूटी इक्ट्ठा करते और जोगीराव बाबा मंदिर पहुंचकर औषधियों की शुद्धि और सिद्धि के लिए पूजा करते.

बालोद। जिले के वनांचल क्षेत्र में लोक आस्था और पारंपरिक ज्ञान का एक अद्भुत दृश्य मंगलवार को देखने को मिला। मान्यता है कि इस विशेष तिथि पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ग्रह-नक्षत्र और पंचतत्व अपने चरम प्रभाव में होते हैं। इसी विश्वास के साथ पारंपरिक औषधि साधक और बैगा-गुनिया जंगलों की खाक छानकर दुर्लभ जड़ी-बूटियां एकत्र करने निकले। औषधियां जुटाने के बाद सभी झलमला स्थित सिद्ध जोगी राव बाबा मंदिर पहुंचे, जहां औषधियों की शुद्धि और सिद्धि के लिए विशेष पूजा-अर्चना की गई। बालोद में ऋषि पंचमी के दिन उनके अनुयायी गुरु धनवंतरी की विद्या पाने और अनोखी सिद्धि करने जंगल पहुंचे। औषधि साधक जंगलों से

लाई गई वनस्पतियों को लेकर सीधे झलमला के जोगी राव बाबा मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। गुरु दुष्यंत सिंह ओटी ने बताया कि छत्तीसगढ़ और मध्य भारत की लोक-परंपरा में %गुरु धनीत्तर% को आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि का ही लोक-अवतार माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार, गुरु धनीत्तर को प्रकृति की हर वनस्पति, पत्ती और जड़ की भाषा का ज्ञान था। कहा जाता है कि गुरु धनीत्तर जब जंगलों से गुजरते थे, तो वनस्पतियां स्वयं पुकारकर अपने भीतर छिपे रोगनाशक गुणों को प्रकट करती थीं। तक्षक नाग और विष-हरण से जुड़ी लोक-गाथाओं में भी गुरु धनीत्तर को असाध्य रोगों और सर्पदंश के अचूक ज्ञाता के रूप में पूजा जाता है। आदि-गुरु के रूप में वे केवल औषधि ही नहीं, बल्कि वनस्पति को जागृत करने वाले मंत्र-विधान के प्रणेता भी माने जाते हैं। पुजारी दीनबंधु ठाकुर ने बताया कि जोगीराव बाबा मंदिर का महत्व परंपराओं से जुड़ा है। मान्यता है कि ऋषि पंचमी के दिन लाई गई जड़ी-बूटियों को जब गुरु धनीत्तर और जोगी राव बाबा के चरणों में अर्पित किया जाता है, तो उनका औषधीय प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तंत्र व विष-विद्या के निवारण से जुड़े साधक यहां नाग-नागिन के जोड़ों की विशेष पूजा करते हैं, जो गुरु धनीत्तर की सर्प-दंश निवारक परंपरा का ही प्रतीक है। मंदिर पहुंचे साधकों ने बताया कि यह वार्षिक अनुष्ठान उनके लिए केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि अपनी गुरुकुल परंपरा के प्रति कृतज्ञता है। जंगलों में नई पीढ़ी के शिष्यों को ले जाकर दुर्लभ पौधों की पहचान कराना और उनके गुण सिखाना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है।

छत्तीसगढ़ के लोकेंद्र ने सूर्यकुमार यादव को दिया अनोखा बर्थडे गिफ्ट

मुंबई पहुंचकर आदमकद प्रतिमा की भेंट

बालोद। क्रिकेट के प्रति जुनून और शहीदों के सम्मान की अलग मिसाल पेश करने वाले बालोद जिले के देवगहन गांव निवासी लोकेंद्र साहू एक बार फिर चर्चा में हैं। लोकेंद्र साहू ने अपनी निजी जमीन पर आतंकी हमलों और अलग-अलग जगहों पर शहीद हुए 18 शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित कर रखी हैं। इसी जमीन पर उन्होंने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा भी लगाई है। अब लोकेंद्र साहू ने भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव की करीब दो लाख रुपए की लागत से आदमकद प्रतिमा बनवाई है। सूर्यकुमार यादव के जन्मदिन के मौके पर प्रतिमा लेकर लोकेंद्र मुंबई के चेंबूर स्थित उनके घर पहुंचे और उन्हें यह प्रतिमा भेंट की। सूर्यकुमार यादव से मुलाकात के दौरान लोकेंद्र ने अपनी पहल के बारे में बताया और उनसे अपनी निजी जमीन पर स्थापित 18 शहीदों की प्रतिमाओं का अनावरण करने का आग्रह किया। लोकेंद्र की इस पहल की सूर्यकुमार यादव ने तारीफ की। उन्होंने छत्तीसगढ़ आने पर लोकेंद्र से मुलाकात करने का वादा भी किया। मुलाकात के दौरान सूर्यकुमार यादव ने लोकेंद्र से कहा कि जहां उन्होंने सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा लगाई है, वहीं उनकी प्रतिमा भी स्थापित कर दी जाए। सूर्यकुमार की इस बात के बाद लोकेंद्र उनकी प्रतिमा को लेकर वापस छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं। यहां पहुंचने के बाद वे अपनी निजी जमीन पर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा के पास सूर्यकुमार यादव की प्रतिमा स्थापित करेंगे।

मछली पालन का आधुनिक तरीका, बायोफ्लॉक तकनीक से कोरबा के किसान बढ़ा रहे आय

कोरबा। जिले के किसान अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर खेती कर रहे हैं। जिले के कटघोरा और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में किसानों ने बायोफ्लॉक (क्द्ब्श्द्धद्यश्ष) तकनीक अपनाकर मछली पालन की शुरुआत की है। कम लागत, सीमित जगह और बंपर पैदावार के दम पर यहां के किसान एक साल के भीतर ही लाखों रुपये का मुनाफा कमाने में कामयाब हो रहे हैं।

कम जगह और तिरपाल के तालाब व टैंकों में ?बायोफ्लॉक तकनीक पारंपरिक तालाबों से बिल्कुल अलग है। इसमें प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं के तालाब विकसित किए जाते हैं जिससे अच्छी पैदावार होती है। जमीन पर लोहे या बांस के ढांचे के सहारे भी इस तकनीक से मछली पालन किया

जा सकता है। गांव रंजना के किसान संजय पटेल का कहना है कि उन्होंने बायोफ्लॉक तकनीक से तीन तालाब तैयार किए हैं। जिसमें वर्तमान में 50 से 60 टन बड़ी मछलियां मौजूद हैं। वे मछली बीज का भी उत्पादन करते हैं जिसे लेने के लिए पड़ोसी जिले से भी लोग अब उनके पास आते हैं। दरअसल, ?पारंपरिक मछली पालन में मछलियों द्वारा खाए गए दाने का लगभग 75त्न हिस्सा मल-मूत्र और कचरे के रूप में पानी में मिलकर अमोनिया गैस बनाता है, जो मछलियों के लिए हानिकारक होता है। लेकिन बायोफ्लॉक में पानी के अंदर गुड़ और प्रोबायोटिक्स (लाभदायक बैक्टीरिया) मिलाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया जहरीले अमोनिया को प्रोटीन युक्त सूक्ष्म जीवों के गुच्छों यानी फ्लॉक में बदल देते हैं। जिससे मछली के दाने का खर्च भी 20 से 30 प्रतिशत तक कम हो जाता है। बायोफ्लॉक तकनीक के लिए बड़े टैंक या ढांचा भी बनाया जाता है और तालाब खोदकर इसमें तिरपाल बिछाया जाता है। संजय पटेल ने कहा कि मैंने तालाब खोलकर इसमें अच्छी क्वालिटी का तिरपाल बिछाया है और इसी के अंदर मछली पालन हो रहा है। विभाग के अनुसार सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कम से कम 25-30 डिसमिल जमीन होनी चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति चाहे तो इससे कम जमीन पर भी अपने खर्चे पर इस तकनीक का इस्तेमाल कर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। कटघोरा क्षेत्र के सक्रिय मछली फार्म्स में संजय पटेल के अलावा और भी कई किसान जुड़े हुए हैं। मछली पालन विभाग के अनुसार 25 से 30 डेसिमल पर जमीन पर तालाब का निर्माण करना चाहिए, जिसकी कुल लागत 14 लाख रुपए है, जिसमें महिला हितग्राही को 60% तक अनुदान मिलता है। जबकि एसटी, एससी और सामान्य वर्ग के लिए भी अनुदान की पात्रता है। सामान्य वर्ग के हितकारी को भी 40 से 50 फीसदी तक का अनुदान मिल जाता है। इस हाई-टेक प्रणाली में मुख्य रूप से उन प्रजातियों का चयन किया जा रहा है जो तेजी से बढ़ती हैं और बाजार में जिनकी भारी डिमांड है। इनमें प्रमुख रूप से पंगेसियस, कतला और रोहू, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प सहित तिलापिया मछली का भी पालन हो रहा है। ये तेजी से शारीरिक विकास करने वाली प्रजातियां हैं। पंगेसियस जैसी मछलियां महज 5 से 7 महीने के भीतर बाजार में बिक्री के लिए तैयार हो जाती हैं।बायोफ्लॉक तकनीक मछली पालन की एक आधुनिक और अत्यधिक लाभप्रद तकनीक है। जिसमें जमीन के बड़े प्राकृतिक तालाबों की जगह कम जगह में कृत्रिम टैंक या जमीन पर तिरपाल/पॉलीलाइनर बिछाकर बनाए गए तालाबों का उपयोग किया जाता है। ?सामान्य जमीन पर पानी टिक नहीं पाता और रिसकर नीचे चला जाता है। इसलिए जमीन पर गड्ढा खोदकर क्क्कुष्ट तिरपाल बिछाया जाता है। तिरपाल लगाने से पानी का संपर्क सीधी मिट्टी से नहीं होता, जिससे पानी गंदा नहीं होता, प्रबंधन आसान हो जाता है।

90 साल की वृद्ध महिला ने लगाई न्याय की गुहार

सूरजपुर। बुढ़ापे में जिस महिला को सहारा मिलना था, उसे ही परिजन प्रताड़ित कर रहे हैं। सूरजपुर जिले में गणेशपुर गांव में 90 साल की बुजुर्ग महिला किसी तरह जनपद कार्यालय पहुंची और परिजनों की प्रड़ातना से बचाने की गुहार लगाई। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल बुजुर्ग महिला को अस्पताल भिजवाया।

बुजुर्ग महिला ने अपने परिजनों पर कथित तौर पर मारपीट करने और गर्म पानी डालने का आरोप लगाया है। इससे उनकी पीठ बुरी तरह से

झुलस गई। वहीं आंख के ऊपर चोट लगने से खून बह रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। अधिकारियों ने मामले की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को दी और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इस बीच बुजुर्ग महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस मामले में कब तक जांच शुरू करती है। हालांकि परिजनों पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

15 अक्टूबर के बाद शहर में शुरू होगा डामरीकरण

कोरबा। मानसून के दौरान बारिश और जलभराव के कारण कोरबा शहर से लेकर उपनगरीय क्षेत्रों और अंदरूनी कॉलोनियों तक की सड़कों की स्थिति बेहद जर्जर हो गई है। कई प्रमुख मार्गों पर डामर उखड़ने और बड़े बड़े गड्ढे बन जाने के कारण राहगीरों, वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में जिन गड्ढों में कीचड़ और पानी भर रहा था, अब वहां से धूल उड़ रही है, जिससे लोग परेशान हैं।

शहर की खराब सड़कों की स्थिति का संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री एवं स्थानीय विधायक लखन लाल देवांगन ने इस दिशा में विशेष पहल की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मानसून सीजन और बारिश का दौर थमने के बाद, 15 अक्टूबर के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में सड़कों के डामरीकरण और विशेष मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। उनका दावा है की कागजी प्रक्रिया पूरी करने गई है,

जल्द काम शुरू होगा। सड़कों के कायाकल्प और सुधार के लिए नगर निगम द्वारा कागजी और टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके अंतर्गत शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों और अंदरूनी कॉलोनियों की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए लगभग 27 करोड़ रुपये की लागत से टेंडर जारी किए गए हैं। प्रशासनिक नियमों के मुताबिक 15 अक्टूबर तक डामरीकरण और सड़क निर्माण कार्यों पर तकनीकी रोक रहती है, ताकि बरसात के मौसम में नए कार्य प्रभावित न हों।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जापान के छात्रों ने देखा सिरपुर की ऐतिहासिक धरोहर

महासमुंद। छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में टूरिज्म बोर्ड ने बड़ा काम किया है. छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने जापान के मत्सुयामा स्थित एहिमे यूनिवर्सिटी के 17 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के लिए विशेष हेरिटेज टूर का आयोजन किया। अकादमिक एवं शोध सहयोग के उद्देश्य से 12 से 14 सितंबर 2026 तक एनआईटी रायपुर द्वारा होस्ट किए गए जापानी डेलीगेशन ने 14 सितंबर को प्राचीन ऐतिहासिक नगरी सिरपुर का भ्रमण कर छत्तीसगढ़ की उस विरासत को करीब से जाना, जिसमें बौद्ध, हिंदू और जैन संस्कृति का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। मुख्य हॉस्पिटैलिटी एवं आयोजन सहयोगी के रूप में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के लिए सिरपुर में विशेष हेरिटेज टूर की व्यवस्था की। डेलीगेशन को सिरपुर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्थापत्य कला, पुरातात्विक महत्व और धार्मिक-सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराने के लिए विशेषज्ञ स्थानीय गाइड की सेवाएं ली गईं।

धमतरी में सड़क पर बैठा दिखा तेंदुआ, गांव में अलर्ट

धमतरी। लीलर गांव के पास एक तेंदुआ सड़क पर बैठा मुसाफिरों को नजर आया। लोगों ने जैसे ही तेंदुए को देखा उनके होश उड़ गए। तभी मौके से गुजर रहे एक कार सवार ने सड़क पर बैठे तेंदुए का वीडियो बना लिया। वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, वन विभाग भी हरकत में आ गया। वन विभाग की टीम ने ऐहतियात के तौर पर आस पास के गांव वालों को सावधान रहने की हिदायत दी है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो रात के वक्त बाहर निकलने से या फिर अकेले जाने से बचें। स्थानीय लोगों ने बताया कि आसपास के जंगल में यहां बड़ी संख्या में तेंदुए हैं। खाने और पानी की तलाश में वो कई बार रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच जाते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार तेंदुए के सड़क पार करने की तस्वीरें भी उतारी है। तेंदुए को सबसे पहले देखने वाले कार सवार ने बताया कि पहले तो वो तेंदुए को देखकर डर गए लेकिन कार का शीशा बंद होने की वजह से उनको थोड़ा खतरा कम महसूस हुआ। राहगीर ने बताया कि थोड़ी दर तक तेंदुआ सड़क पर बैठा रहा।

आशीर्वाद का दीया: बिहान दीदियों की अनूठी पहल

एमसीबी। जिले में बिहान योजना के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को संगठित कर आत्मनिर्भरता, सहभागिता और सामुदायिक एकजुटता को बढ़ावा देने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में महिला समूहों द्वारा एक अनूठी और भावनात्मक पहल आशीर्वाद का दीया शुरू की जा रही है। इस पहल के तहत जिलेभर में लगभग 13 हजार संभावित दीदियों को जोडने् के साथ लगभग 17 हजार शेष समूह सदस्यों के घरों में आटे से तैयार हस्तनिर्मित दीये प्रज्ज्वलित करने का संकल्प लिया गया है। आशीर्वाद का दीया अभियान के तहत 17 सितंबर 2026 को शाम 7 बजे बिहान से जुड़ी दीदियां अपने-अपने घरों के आंगन में अपने हाथों से तैयार किए गए आटे के दीये जलाएंगी। इस पहल की खास बात यह है कि दीदियां बाजार से खरीदे हुए दीयों के बजाय आटे से स्वयं हस्तनिर्मित दीये तैयार करेंगी। अपने हाथों से बनाए गए इन दीयों के माध्यम से स्थानीय संसाधनों के उपयोग, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया जाएगा।

महासमुंद में समूह की दीदियां गढ़ रहीं संकल्प के दीये

महासमुंद। मिट्टी को आकार देती उंगलियां, आंखों में आत्मनिर्भरता का सपना और मन में सेवा का संकल्प महासमुंद जिले की महिला स्व-सहायता समूहों की दीदियां इन दिनों कुछ ऐसा ही कर रही हैं। उनके हाथों से आकार ले रहा हर दीया सिर्फ मिट्टी का दीपक नहीं, बल्कि संकल्प, स्वावलंबन और आभार की रोशनी का प्रतीक बन रहा है। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम ने जिले की समूह की महिलाओं के जीवन में भी खुशियों का उजाला किया है। दीयों के मिले बड़े ऑर्डर ने महिलाओं को दीपावली से पहले ही दीपावली मनाने का अवसर दे दिया है। महासमुंद जिले के लड्डू गोपाल स्व-सहायता समूह की दीदियों को 37 हजार दीये बनाने का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा जिले के विभिन्न क्लस्टरों में भी बड़ी संख्या में दीयों के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। खल्लारी क्लस्टर को 8 हजार, खम्हरिया को 7 हजार, कोमाखान को 10 हजार और तेंदुकोना को 9 हजार दीयों का ऑर्डर मिला है। एक दीये की कीमत 1 रुपये निर्धारित है।

जशपुर में जगमगाएंगे 5 लाख से अधिक आशीर्वाद के दीप

जशपुर। सेवा, सुशासन और समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जशपुर जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले में विभिन्न जनकल्याणकारी एवं जनभागीदारी आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के प्रथम दिवस 17 सितंबर को शाम 7 बजे जिले में 5 लाख से अधिक आशीर्वाद के दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। सेवा संकल्प अभियान के प्रथम दिवस जिले के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों रणजीता स्टेडियम, गौरव पथ, महाराजा चौक, दिलीप सिंह जूदेव प्रतिमा चौक और बिरसा मुंडा चौक सहित सभी विकासखंडों, नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जिलेवासी सेवा, सुशासन और जनभागीदारी के संकल्प के साथ अभियान से जुड़ेंगे। महिलाओं सहित शासकीय कार्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं में भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे।

कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं मंत्री, रेत हो या कोयला सब काम मंत्री की अनुशंसा पर: चरण दास महंत

कोरबा। चरणदास महंत ने कहा कि भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता इस सरकार से बेहद नाराज हैं। उन्हें किसी भी काम में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। कमीशन नहीं मिल रहा है, मंत्रिमंडल के एक-दो सदस्य भी उनके संपर्क में हैं। इशारों ही इशारों में महंत ने कोरबा विधायक और मंत्री लखन लाल देवांगन पर भी हमला बोला और कहा कि आपके यहां के मंत्री की ही अनुशंसा पर सभी गलत कार्य हो रहे हैं, इनका भविष्य मुझे उज्जवल नहीं दिख रहा है।

महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों को बहुत तकलीफ है। वह लोग एक दिन भी सरकार को देखना नहीं चाहते। कांग्रेस की मजबूरी है कि ढाई साल उनको देखना पड़ेगा। हमें मालूम है कि कब उनपर हमला बोलना है, कब कार्रवाई करना है, इसलिए हम अभी से मोर्चा नहीं खोलना चाहते। सत्ता किसी से छीन के लूट नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों का हिस्सा छीना जा रहा है, उन्हें उनका महीना नहीं मिल रहा है। न शराब में न रेत में न ट्रांसफर में हिस्सा मिल रहा है, इसलिए वह ज्यादा आक्रोशित हैं।

असंतुष्ट भाजपा नेताओं से संपर्क में रहने वाले प्रश्न पर डॉ महंत ने कहा कि हर आदमी उनके संपर्क में है।

मुख्यमंत्री किसी की सुनते नहीं हैं। उनसे खेत के बारे में पूछो तो वे खलिहान के बारे में बताते हैं। भाजपा में जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वे हमारे संपर्क में हैं। लेकिन अभी से हम कोई तोड़फोड़ करना नहीं चाहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी हमारी बात सुनते हैं। महंत ने कहा कि हमने 136 बिंदु का प्रस्ताव रखा था। लेकिन 136 में से एक बिंदु का भी उन्होंने(सीएम) ने उत्तर नहीं दिया। पूरे समय यह कहने में लग रहे हैं कि आपकी सरकार में यह हुआ, आपकी सरकार में खराब हुआ। आपकी सरकार में काम नहीं हुआ। आपकी सरकार में घर नहीं बना, आपकी सरकार में चावल नहीं बंटा, तो यह बहाने बना बनाकर एक भी प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया और सब पुरानी बात को करके बचते रहे। डीएमएफ के प्रश्न पर कहा कि जब हमारी सरकार थी तब डीएमएफ में घोटाले हुए। हमने सरेआम कहा कि जांच करो। जो भी दोषी हैं, उनको सजा दो और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अभी जो कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, उन लोगों को भी एक दिन जेल में जाना पड़ेगा। इस बात को उनको समझना चाहिए। जो गलती हुई है उसमें तो लोग जेल जा रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, तो हम लोग भी जब सत्ता में आएंगे तब हम भी नहीं छोड़ेंगे।जिन लोगों ने गलतियां की है, उन्हें सजा मिलेगी। रेल सुविधा के प्रश्न पर कहा कि सांसद ज्योत्सना महंत ने कई बार पत्र लिखा, कई बार बोल चुकी हैं। मंत्रियों अधिकारियों से मिलकर रेत सुविधाओं पर बात की। रेलवे के एक अधिकारी ने भी माना कि छत्तीसगढ़ की 70% आय बिलासपुर जोन से हो रही है, लेकिन यहां सुविधा देने में हम पीछे हैं। 20% भी नहीं दे पा रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि ऊपरी स्तर पर गड़बड़ी हुई है। केंद्र स्तर से उसे ठीक करने के लिए बात की है और बहुत जल्द हम रेलवे बोर्ड के साथ अलग से मीटिंग करेंगे। एक प्रश्न के उत्तर में डॉ महंत ने कहा कोरबा में मंत्री हैं, आप खुद देख लो कैसे कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं।

बस्तर ट्राईफूड पार्क बना सिर्फ सपना

बिल्डिंग हो रही खंडहर, वनोपज प्रोसेसिंग कर 30 हजार लोगों को रोजगार देने का प्रोजेक्ट

जगदलपुर। बस्तर में आदिवासियों के लिए रोजगार का सपना दिखाकर खड़ा किया गया ट्राईफूड पार्क आज खुद अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। 30 हजार आदिवासी ग्रामीणों को वनोपज आधारित रोजगार देने का दावा करने वाला यह प्रोजेक्ट चार साल बाद भी सिर्फ कागजों और बयानों तक सिमटकर रह गया है।

करीब 50 करोड़ रुपये की लागत से बना यह ट्राईफूड पार्क न तो रोजगार दे सका और न ही वनोपज का एक भी प्रोसेसिंग प्लांट शुरू हो पाया। आदिवासी अंचल के ग्रामीणों को उम्मीद थी

कि स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट लगने से हजारों लोगों को काम मिलेगा। लेकिन आज हालात ये हैं कि करोड़ों का यह परिसर एक माली एक कर्मचारी और दो गार्ड के भरोसे खड़ा है। ना वनोपज खरीदी शुरू हुई। ना प्रोसेसिंग यूनिट लगी और ना ही आदिवासियों को रोजगार मिला। रख-रखाव के अभाव में भवन भी धीरे-धीरे जर्जर होता जा रहा है।

सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ट्राईफूड पार्क शुरू नहीं होने को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा- साल 2020 में ट्राईफूड पार्क के लिए स्थ्र के बाद भूमि अधिग्रहण किया गया। 50 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत बस्तर में पाए जाने वाले 60 प्रकार के वनोपज का प्रोसेसिंग करके करीब 30 हजार लोगों को रोजगार से जोड़ना था। साल 2021 में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा प्लांट की समीक्षा करने बस्तर पहुंचे। इसके बाद भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। 6 साल पहले बिल्डिंग बनाई गई जो अब जर्जर हालत में है।

संभागीय अध्यक्ष ने बताया कि इसमें इमली प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है, जिसमें काम नहीं हो रहा है। मशीन रखरखाव के अभाव में खराब हो रही है।

विरासत, विकास और विश्वास

की नई यात्रा में

छत्तीसगढ़ की उपलब्धियां

अतीत की अमूल्य धरोहर से भविष्य के विकसित छत्तीसगढ़ तक

> “छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी गौरवशाली विरासत, समृद्ध जनजातीय संस्कृति और हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता से है। हमारी सरकार विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। कांगेर वैली को वैश्विक पहचान दिलाने से लेकर मल्हार, सिरपुर और प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण तक, हम अपनी जड़ों को सहेजते हुए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी विरासत पर गर्व करें और विकास के नए अवसरों से भी जुड़ें।”
> — विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ आज केवल प्राकृतिक संसाधनों और जनजातीय संस्कृति की भूमि भर नहीं है, बल्कि यह अपनी हजारों वर्षों पुरानी विरासत, तेज़ी से विकसित होती अधोसंरचना और जनकल्याणकारी योजनाओं के बल पर नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार एक ओर जहां अपनी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित कर रही है, वहीं दूसरी ओर विकास और जनविश्वास के नए आयाम भी स्थापित कर रही है। राज्य की यह यात्रा केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ने की एक ऐसी विकासगाथा है, जिसमें विरासत, विकास और विश्वास तीनों समान रूप से शामिल हैं।

विरासत का वैभव

हजारों वर्षों के इतिहास को संजोता छत्तीसगढ़

शैलचित्रों की धरती

सिंहनपुर, कबरा पहाड़ (रायगढ़), चितवाड़ोंगरी (बालोद) और चरामा (कांकेर) के प्रागैतिहासिक शैलचित्र मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। चरामा में मिले लगभग 10,000 वर्ष पुराने चित्र विश्वभर के शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र हैं।

सिरपुर की प्राचीन सभ्यता

महानदी के तट पर स्थित सिरपुर 5वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहां 12 बौद्ध विहार, प्राचीन लक्ष्मण मंदिर, मठ, मूर्तियां और भूमिगत स्नानगृह के अवशेष मिले हैं।

ताला की रूद्रशिव प्रतिमा

बिलासपुर जिले के ताला स्थित देवरानी-जेठानी मंदिर परिसर से प्राप्त रूद्रशिव प्रतिमा युप्तकालीन कला का अद्वितीय उदाहरण है, जिसमें अनेक जीव-जंतुओं के स्वरुप शिव की विराट कल्पना को दर्शाते हैं।

मल्हार के ताम्रपत्र

बिलासपुर के मल्हार में मिले लगभग 1400-1500 वर्ष पुराने ताम्र-पट्टिकाएं भारतीय इतिहास के लिए अमुल्य धरोहर हैं। इन पर अंकित ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में शासन, संस्कृति और सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।

अन्य पुरातात्विक स्थलों की पहचान

दीपादीह (सरगुजा), पचराही (कबीरधाम), करकाभाट (बालोद) और तरीघाट (दुर्ग) जैसी जगहें महापाशाणकाल से मध्यकालीन इतिहास तक की धरोहरों को संजोए हुए हैं।

छत्तीसगढ़ की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरें

- सिंहनपुर और कवरा पहाड़ (रायगढ़)
- चितवाडोंगरी (बालोद)
- चरामा (कांकेर)
- सिरपुर (महासमुंद)
- ताला - देवरानी-जेठानी मंदिर (बिलासपुर)
- दीपादीह (सरगुजा)
- पचराही (कबीरधाम)
- करकाभाट (बालोद)
- तरीघाट (दुर्ग)

अनूठी जैव-विविधता प्रदेश की अद्वितीय पहचान

वैश्विक पहचान की दहलीज पर

यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल कांगेर वैली

बस्तर स्थित कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची (Tentative List) में शामिल किया गया है। कोटमसर, कैलाश और दंडक गुण्णाएं, दुर्लभ वन्यजीव, 900 से अधिक वनस्पति प्रजातियां, 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां और अनूठी जैव-विविधता इसे विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाती हैं। यह उपलब्धि पर्यटन, स्थनीय रोजगार और जनजातीय समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण के नए अवसर पैदा करेगी।

लोक संस्कृति और परंपराएं

हमारी पहचान, हमारी आत्मा

- 35 से अधिक जनजातीय समुदायों की समृद्ध संस्कृति
- पंडवानी, राउत नाचा, सुवा नृत्य, करमा, दीवारी जैसे लोकनृत्य
- बस्तर कला, ढोकरा शिल्प, बॉस और लकड़ी की कला का संरक्षण
- ग्रामीण और इको-टूरिज्म के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को आर्थिक अवसरों से जोड़ना

विकास के नए आयाम

आधुनिक छत्तीसगढ़ की पहचान

नई विधानसमा - नए संकल्प

नवा रायपुर में बना अत्याधुनिक विधानसमा भवन लोकतंत्र, पारदर्शिता और आधुनिक तकनीक का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की विकास यात्रा का गौरवपूर्ण अध्याय बताया।

शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव विकास

राज्य में IIT, IIM और AIIMS जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं की उपस्थिति से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है।

सतत विकास लक्ष्य (SDG) में उत्कृष्ट प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिले ‘फ्रंट रनर’ श्रेणी में शामिल होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक विकास के क्षेत्र में मिसाल कायम कर रहे हैं।

जनजातीय उत्थान की मजबूत पहल

प्रधानमंत्री जनमन अभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में पक्का आवास, बिजली, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है।

खेल प्रतिभाओं को मिल रही पहचान

जशपुर के युवा धावक अनिमेष कुजूर ने 100 मीटर दौड़ में 10.15 सेकंड का रिकॉर्ड बनाकर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अपनी जगह निति की प्रधानमंत्री द्वारा ‘मन की बात’ में उनका उल्लेख प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है।

छत्तीसगढ़ की प्रमुख उपलब्धियां

- ✓ कांगेर वैली को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल।
- ✓ नई और अत्याधुनिक विधानसभा भवन।
- ✓ सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में अग्रणी जिले।
- ✓ IIT, IIM और AIIMS जैसी राष्ट्रीय संस्थाएं।
- ✓ प्रधानमंत्री जनमन अभियान।
- ✓ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान।
- ✓ खेल, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान।

संवाद-48873/2

→ विरासत से शक्ति • विकास से समृद्धि • विश्वास से भविष्य ←

बस्तर-सरगुजा सहित प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक बैंकिंग नेटवर्क का करें विस्तार: मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में एचडीएफसी बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एचडीएफसी बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाओं के 25 वर्ष पूर्ण किए जाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस उपलब्धि पर बैंक प्रबंधन, अधिकारियों-कर्मचारियों और ग्राहकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने बैंक के छत्तीसगढ़ में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तैयार किए गए विशेष लोगो का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने एचडीएफसी बैंक के छत्तीसगढ़ में 25 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष लोगो का किया विमोचन

मुख्यमंत्री श्री साय ने बैंक के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी प्रदेश की आर्थिक प्रगति में मजबूत और सर्वसुलभ बैंकिंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिछले वर्षों में बैंकिंग सेवाओं में तेजी से विस्तार हुआ है और डिजिटल तकनीक ने वित्तीय सेवाओं को पहले से अधिक सहज बनाया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ केवल बड़े शहरों और व्यावसायिक केंद्रों तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक भी समान रूप से पहुंचे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बैंकिंग नेटवर्क का और विस्तार करते हुए विशेष रूप से बस्तर एवं सरगुजा अंचल के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण और जनजातीय बहुल है। इन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता बढ़ने से लोगों को आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने के अधिक अवसर मिलेंगे और सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी अधिक सुगमता से उन तक पहुंच सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गांव के नजदीक बैंक की शाखा या बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होने का प्रभाव केवल बैंकिंग लेन-देन तक सीमित नहीं रहता। इसके दूरगामी सामाजिक और आर्थिक परिणाम होते हैं। ग्रामीणों को अपने खाते से संबंधित सामान्य कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, उनका समय और संसाधन बचता है तथा बचत और औपचारिक बैंकिंग के प्रति उनका विश्वास बढ़ता है। ऋण, बीमा, डिजिटल भुगतान और अन्य वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच मिलने से परिवारों के आर्थिक सशक्तीकरण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज केंद्र और राज्य सरकार की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंच रही है। ऐसे में अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं की सहज उपलब्धता सुशासन की व्यवस्था को भी मजबूत करती है। बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार का लाभ नागरिकों के साथ-साथ शासन को भी मिलता है, क्योंकि इससे योजनाओं का लाभ पारदर्शी, सुरक्षित और समयबद्ध ढंग से हितग्राहियों तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा आती है। किसानों को कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता, युवाओं को स्वरोजगार और उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण तथा छोटे व्यवसायियों को अपने कारोबार के विस्तार के लिए पूंजी आसानी से उपलब्ध हो सकती है। इससे गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी तैयार होते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने महिला स्व-सहायता समूहों की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं आज स्व-सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न आजीविका गतिविधियों और छोटे उद्यमों से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बैंकिंग संस्थाएं यदि इन समूहों तक ऋण, वित्तीय साक्षरता और अन्य बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच को और मजबूत करें तो महिलाओं की उद्यमशीलता को बड़ा संबल मिल सकता है। आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं अपने परिवार के साथ पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

घर-घर पहुंचीं महिलाएं, मिट्टी के दीये जुटाकर जनभागीदारी का दिया संदेश

सेवा संकल्प अभियान : 'आशीर्वाद का दीया' के लिए बिहान दीदियों ने जगाई जन-अलख

रायपुर। शासकीय योजनाएं तब जन-आंदोलन का रूप लेती हैं, जब समाज का हर वर्ग उनमें अपनी सहभागिता निभाता है। बालोद जिले में सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत कुछ ऐसा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर को आयोजित होने वाले 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम को लेकर बिहान स्व-सहायता समूह की दीदियों ने जनजागरूकता की अनूठी मिसाल पेश की है।

बालोद विकासखंड की बिहान समूह से जुड़ी महिलाएं गांव-गांव और घर-घर पहुंचीं। उन्होंने ग्रामीणों से स्वेच्छा से मिट्टी के दीये और बाती एकत्र किए और परिवारों को सेवा संकल्प अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। दीदियों के आत्मीय आग्रह से ग्रामीण भी उत्साह के साथ इस पहल से जुड़े और कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाने का संकल्प लिया।

दीदियों के प्रयास से गांवों में बना उत्सव का माहौल

बिहान समूह की श्रीमती विनीता साहू और श्रीमती रवीना साहू ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल दीये एकत्र करना नहीं, बल्कि जनसेवा, सुशासन और जनभागीदारी की भावना को घर-घर तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि दीदियों ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए उन्हें 17 सितंबर को 'आशीर्वाद का दीया' जलाने और सेवा संकल्प अभियान में सहभागी बनने के लिए भी प्रेरित किया। दीदियों की इस पहल से गांवों में जहां उत्साह का माहौल बना है वहीं ग्रामीणों ने स्वेच्छा से मिट्टी के दीये उपलब्ध कराए और अभियान से जुड़ने की इच्छा जताई। इससे यह संदेश भी सामने आया कि जब महिलाएं जागरूकता की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेती हैं, तो ऐसे महत्वपूर्ण अभियानों में जनभागीदारी और अधिक मजबूत होती है।

जनजागरूकता में बिहान दीदियों की सशक्त भूमिका

बिहान स्व-सहायता समूह की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका गतिविधियों के साथ-साथ विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक अभियानों में भी सक्रिय सहभागिता निभा रही हैं। 'आशीर्वाद का दीया' के लिए घर-घर जाकर लोगों को जोड़ने की यह पहल महिला सशक्तिकरण और जनभागीदारी का प्रेरक उदाहरण बन रही है। 17 सितंबर की शाम जब 'आशीर्वाद का दीया' प्रज्वलित होगा, तो उसकी रोशनी में केवल मिट्टी के दीये ही नहीं, बल्कि बिहान दीदियों के जनजागरूकता के जज्बे, ग्रामीणों की सहभागिता और सेवा के प्रति सामूहिक संकल्प की चमक भी दिखाई देगी।

आजीविका गतिविधियों के माध्यम से जीवन में आया सकारात्मक बदलाव

बिहान की दीदियों ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर वे आज आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनी हैं। आजीविका गतिविधियों के माध्यम से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और समाज में उन्हें नई पहचान व सम्मान मिला है। इस संबल और स्वावलंबन के लिए समूह की महिलाओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति सहृदय आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है।

रायपुर ओपन: खलिन जोशी ने बनाई 2 शॉट की बढ़त, टॉप पर कायम

रायपुर। नवा रायपुर के फेयरवे गोल्फएंड लेक रिजॉर्ट में खेले जा रहे, ओपन के दूसरे राउंड में बेंगलुरु के खलिन जोशी ने बोगी-मुक्त 4-अंडर 30 का स्कोर बनाकर दो शॉट की बढ़त बना ली है। हाफ्वे तक जोशी 9-अंडर 59 के साथ लीड पर हैं। जानकारी के अनुसार भारी बारिश के कारण कोर्स 18 होल के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए टूर्नामेंट समिति ने चारों राउंड बैक नाइन पर 9-9 होल में कराने का फैसला किया है। वहीं, ओपन में जीतने वाले को एक करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि एक शॉट की बढ़त के साथ दिन की शुरुआत करने वाले 34 वर्षीय जोशी (29-30) ने दूसरे राउंड में 4 बर्डी लगाईं और लगातार दूसरे दिन एक भी बोगी नहीं की। इस सीजन में क्क्त्रञ्ज पर दो खिताब जीत चुके जोशी ने कहा- यह एक और ठोस राउंड रहा, टी से ग्रीन तक मेरा खेल मजबूत रहा है। दूसरे स्थान पर कोलकाता के 20 वर्षीय आर्यव शाह (30-31) 7-अंडर 61 के साथ नेपाल के सुभाष तमांग (32-29), बेंगलुरु के अक्षय निरंजन (30-31) और पंचकूला के रौनिल कुकर (31-30) के साथ संयुक्त रूप से हैं। तमांग ने 5 बर्डी के साथ बोगी-मुक्त 29 का स्कोर किया, जो दिन का संयुक्त सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा। 56 खिलाड़ियों ने कट पार किया, जो 3-अंडर 65 पर लगा।

6-अंडर 62 के साथ संयुक्त छठे स्थान पर 7 खिलाड़ी हैं, जिनमें वीर अहलावत, सुनीत चौरसिया और उमेद कुमार शामिल हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

सरकारी विभागों में एक लाख सात हजार पद खाली- कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा को सरकार में आए ढाई साल हो गया है जब भाजपा सरकार में आई है युवाओं के लिए सरकारी भर्तियां निकलना बंद हो गई ।प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में एक लाख सात हजार पद खाली है सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है ।भाजपा सरकार से सवाल किया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं से किए गए एक लाख सरकारी नौकरियों के वादे का क्या हुआ? भाजपा ने चुनाव के समय मोदी की गारंटी में वादा किया था। अब 5 साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने सरकार को प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को बताना चाहिए कि उस गारंटी की नौकरी कब मिलेगी? भाजपा को सत्ता में आए ढाई साल बीत चुका है, प्रदेश में सरकारी विभागों के एक लाख से अधिक पद रिक्त बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर प्रदेश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सबसे चिंताजनक स्थिति शिक्षा विभाग की है। प्रदेश में लगभग 53 हजार शिक्षक पद रिक्त बताए जा रहे हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है और दूसरी ओर लाखों शिक्षित बेरोजगार युवा नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस का सवाल है कि जब पद खाली हैं, तो सरकार नियमित भर्ती क्यों नहीं कर रही? उच्च शिक्षा विभाग में भी लगभग 3 हजार पद रिक्त हैं।

80 हितग्राहियों के बुनाई प्रशिक्षण के लिए 27.20 लाख स्वीकृत

रायपुर। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार ग्रामोद्योग विभाग ने नक्सल पुनर्वास केंद्रों में नवीन बुनाई प्रशिक्षण के लिए 27.20 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। बस्तर संभाग के 4 केंद्रों के 80 हितग्राहियों को हथकरघा के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।

ग्रामोद्योग विभाग के सचिव सह संचालक सह प्रबंध संचालक राजेश सिंह राणा द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में समग्र हाथकरघा विकास योजना के तहत 11 सितंबर 2026 को यह स्वीकृति जारी की गई है। प्रत्येक केंद्र के लिए 6.80 लाख रुपये का आबंटन किया गया है। विभाग के अनुसार इस पहल से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवा और पुनर्वासित परिवार पारंपरिक बुनाई कला के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकेंगे और समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे।

योजना के तहत -कोंडागांव - देवखरगांव पुनर्वास केंद्र: 20 हितग्राहियों के प्रशिक्षण के लिए चंदेनी बुढ़ीमाता बुनकर सहकारी समिति मर्यादित सलना, कोंडागांव को 6.80 लाख रुपये ।नारायणपुर - गारंजी पुनर्वास केंद्र: 20 हितग्राहियों के प्रशिक्षण के लिए इसी समिति को 6.80 लाख रुपये।

दंतेवाड़ा - नक्सल पुनर्वास लाइवलीहुड कॉलेज: 20 हितग्राहियों के कौशल विकास के लिए कंकालीन बुनकर सहकारी समिति मर्यादित बजावण्ड, बस्तर को 6.80 लाख रुपये।

सरकार के आदेश के बावजूद प्रवेश नहीं, एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन

रायपुर। राज्य सरकार के लिखित आदेश के बावजूद पीआरएसयू सहित अन्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों के छात्रों को सेकंड, थर्ड ईयर और थर्ड-फिफ्थ सेमेस्टर में प्रवेश नहीं मिलने पर एनएसयूआई ने बुधवार को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कुलपति और रजिस्ट्रार के मौके पर नहीं मिलने पर छात्र नेताओं ने नाराजगी जताई और अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। एनएसयूआई, पीआरएसयू अध्यक्ष पुनेश्वर लहरे के नेतृत्व में कार्यकर्ता और छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से मिलकर प्रवेश की समस्या के तत्काल समाधान की मांग की। छात्र नेताओं के धरने पर बैठने के ऐलान के बाद पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन मौके पर पहुंचा और समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्र धरने से पीछे हटे। पुनेश्वर लहरे ने बताया कि राज्य सरकार ने छात्रों को अगले वर्ष और सेमेस्टर में प्रवेश देने का लिखित आदेश जारी किया है, फिर भी छात्रों को परेशान किया जा रहा है। क्रेडिट स्कोर के आधार पर क्क. रूक्क सहित अन्य कोर्स के छात्रों को सेकंड और थर्ड ईयर में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, जिससे हजारों छात्रों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि राज्य सरकार के आदेश का पालन करते हुए छात्रों को बिना शर्त wnd-xrd Year और xrd-zth Semester में नियमित प्रवेश दिया जाए, केवल क्रेडिट स्कोर के आधार पर प्रवेश से वंचित न किया जाए.

असामाजिक तत्वों पर शिकंजा 2 दिन में 10 बदमाश गिरफ्तार

रायपुर। कमिश्नरेट के मध्य जोन में गुंडागर्दी, अवैध वसूली और चाकूबाजी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस ने पिछले दो दिनों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 7 आरोपियों से

धारदार चाकू बरामद हुए हैं, वहीं एक आर्म्स एक्ट का स्थाई वारंटी और अवैध शराब व गुंडागर्दी के मामले में भी कार्रवाई की गई है। डीसीपी सेंट्रल तारकेश्वर पटेल के निर्देश और एडिशनल डीसीपी विवेक शुक्ला के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई ।पुलिस ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थान पर हथियार लेकर घूमने और गुंडागर्दी करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। थाना गंज - 3 गिरफ्तार: इकबाल शेख (21) को एक्सप्रेस-वे चुनाभट्ठी, शिवा नायक उर्फ छुरा (19) को पुरानी शराब भट्ठी के पास लोगों को डराते हुए और नितिन हरिजन उर्फ बिड़ी (21) को तेलघानी नाका ओवरब्रिज के नीचे चाकू के साथ पकड़ा गया। तीनों पर आर्म्स एक्ट 25, 27 के तहत कार्रवाई।

थाना मौदहापारा - 5 पर कार्रवाई: फिरोज खान (33) मेकाहारा स्लम, देवराम बघेल (25) मरही माता मंदिर रोड, मयंक सोनी (19) और युवराज रक्सेल (18) बॉम्बे मार्केट के पास चाकू के साथ पकड़े गए।

निगरानी बदमाश समेत 2 शातिर चोर गिरफ्तार, 3.50 लाख बरामद

रायपुर। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी में सूने मकान का शटर काटकर लाखों के जेवरात और नगदी चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और पुरानी बस्ती पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों से सोने-चांदी के जेवर, सिक्के, नगदी और घटना में प्रयुक्त बुलेट सहित करीब 3.50 लाख रुपये का मशरूका बरामद किया गया है।

प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 अगस्त को वह घर में ताला लगाकर बाहर गया था। 31 अगस्त को काम वाली बाई ने शटर कटा होने और सामान बिखरा होने की सूचना दी। 1 सितंबर को वापस आने पर अलमारी से चांदी की ईंट, सोने-चांदी के जेवर, सोने के सिक्के, चेन, ब्रेसलेट, मोती का हार, मोबाइल सहित सामान चोरी होना पाया गया। रिपोर्ट पर थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्र. 457/26 धारा 331(4), 305 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया।

डीसीपी क्राइम स्मृतिक राजनाला और डीसीपी पश्चिम रॉबिन्सन गुरिया के निर्देश पर एंटी क्राइम और थाना पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पूर्व में चोरी के मामलों में जेल से छूटे आरोपियों पर निगरानी रखी।

छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव विकास शील ने भी सम्मेलन को संबोधित किया

राज्यपाल ने किया राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का शुभारंभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर अटल नगर में 32वें अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का आज भव्य शुभारंभ हुआ। लगभग 11 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद छत्तीसगढ़ को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिला है। सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने दीप प्रज्वलित कर किया।

शुभारंभ समारोह के विशेष अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ स्थानीय निकाय चुनाव 2025-26 के प्रथम संस्करण का विमोचन भी किया। यह प्रकाशन छत्तीसगढ़ में स्थानीय

निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया, उपलब्धियों, नवाचारों और चुनावी व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करता है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने स्थानीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सशक्त, पारदर्शी, समावेशी और तकनीक-सक्षम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और इनके निर्वाचन की प्रक्रिया में निरंतर सुधार तथा आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग आवश्यक है।

इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने सम्मेलन में देशभर से आए राज्य निर्वाचन आयुक्तों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं निर्वाचन विशेषज्ञों का स्वागत करते हुए सम्मेलन के उद्देश्यों और स्थानीय निकाय निर्वाचन को अधिक प्रभावी एवं आधुनिक बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव विकास शील ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने तथा प्रशासन और निर्वाचन संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय के महत्व पर अपने विचार रखे। सम्मेलन के दौरान स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनावों से जुड़े समसामयिक विषयों, डिजिटल पहलों, तकनीकी नवाचारों तथा निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के उपायों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जा रहा है।

समारोह में राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह एवं आयोग की सचिव शिखा राजपूत तिवारी सहित आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और अतिथियों का स्वागत किया। सम्मेलन के प्रथम दिन डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग, निर्वाचन प्रबंधन में नवाचार, पारदर्शिता तथा स्थानीय निकाय निर्वाचन की प्रक्रियाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने से जुड़े विभिन्न विषयों पर परिचर्चा की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्तों की स्थायी समिति के अध्यक्ष विजय देव ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

अवैध निर्माण पर रावतपुरा कॉलोनी में 40 मकानों पर चला बुलडोजर

रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को नगर निगम की टीम ने रावतपुरा फेस-2 कॉलोनी में बिना नक्शा पास कराए लगभग 40 मकानों पर बुलडोजर चलाया। आरोप है कि इन मकानों का निर्माण नगर निगम से नक्शा स्वीकृत कराए बिना कराया गया। नोटिस जारी किए जाने के बाद ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। निगम के अमले ने बुलडोजरों की मदद से चिन्हित अवैध निर्माण को हटाया। कार्रवाई के लिए नगर निगम का अमला मौके पर मौजूद रहा। नगर निगम के अधिकारियों के

मुताबिक, रावतपुरा फेस-2 में करीब 40 मकानों को अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। जानकारी के अनुसार करीब एक दर्जन बुलडोजरों के साथ निगम की टीम रावतपुरा फेस-2 पहुंची थी। जहां बड़ी संख्या में निगम कर्मचारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई ।वहीं, रावतपुरा में नगर निगम की तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि 40 मकान एक दिन में नहीं बने, मकान बनने तक निगम के अधिकारी क्या कर रहे थे, यह कार्रवाई नहीं वसूली पूरी न होने का नतीजा लगती है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.